भारत के सुदृढ़ भविष्य के लिए

MIDHANI

संकल्प

मिधानि की छहमाही राजभाषा गृह पत्रिका

वर्ष 16, अंक 30, अक्तूबर 2024 - मार्च 2025

ई-पत्रिका अंक 10

गाँव, शहर और प्रदूषण विशेषांक

मिधानि के नव वर्ष कैलेंडर का श्री टी. मुत्तुकुमार, निदेशक (उ. एवं वि.) द्वारा विमोचन

दाएँ से बाएँ – हरिकृष्ण वी., अ.म.प्र. (प्रभारी मा.संसा.), के. आनंद कुमार, म.प्र. (पी–II व IV), पी. शशिधरण, म.प्र. (ई.एस), के. मधुबाला, म.प्र. (वित्त एवं लेखा), टी. मुत्तुकुमार, निदेशक (उ. एवं वि.), अरूण कुमार शर्मा, म.प्र. (विपणन), पी. बाबू, म.प्र. (टीएस), डॉ. बी. बालाजी, प्रबंधक (हिं.अ. एवं नि.सं.), महमूद शरीफ, उ.म.प्र. (डीपीएम सचिवालय)

एयरो इंडिया 2025 के दौरान मिधानि के अधिकारी गण माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित

माननीय रक्षा मंत्री के सामने वाली लाइन में बाएँ से दाएँ (2 व 3 स्थान पर) - सांतनु साहा, उ.म.प्र. (पीए) और बी.वी.एस. रामकृष्ण राव, उ.म.प्र. (टाइटेनियम)

संपादक मंडल

प्रधान संरक्षक

डॉ. एस.वी.एस. नारायण मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

सीए एन. गौरी शंकर राव
निदेशक (वित्त)

श्री टी. मुत्तुकुमार
निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)

परामर्शदाता

श्री हरिकृष्ण वी.
अपर महाप्रबंधक (प्रभारी मानव संसाधन)

संपादन व डिजाइनिंग

डॉ.बी.बालाजी
प्रबंधक
हिंदी अनुभाग एवं निगम संचार
तथा सदस्य-सचिव,
राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संपादन सहयोग

श्रीमती डी.वी. रत्न कुमारी
कनिष्ठ कार्यपालक (हिंदी अनुभाग)

श्री वासुदेव
वरिष्ठ सहायक (हिंदी अनुवादक)

संपादक संकल्प

मिश्र धातु निगम लिमिटेड,
कंचनबाग, हैदराबाद-500058
ई-मेल : b.balaji@midhani-india.in
टेलीफोन : 040-24184325, 4298
(मो) 8500920391

पत्रिका केवल आंतरिक वितरण एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए नि:शुल्क है। पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे संपादक मंडल या मिधानि प्रबंधन का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

MIDHANI

संकल्प

मिधानि की छहमाही राजभाषा गृह पत्रिका

इस अंक में

- संदेश... 02
- संपादकीय... 06
- राजभाषा... 07
- आवरण कथा... 14
- कविता कुंज... 26
- आलेख... 28
- कहानी... 35
- गतिविधियाँ... 36

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से...

डॉ. एसवीएस नारायण मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
कंचनबाग, हैदराबाद–500 058
फोन नं.–040–24184501
ई–मेल: cmd@midhani-india.in

प्रिय साथियो,

मिधानि परिवार से जुड़ते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस महान संस्थान के उत्कर्ष में योगदान देने का अवसर पाकर मैं स्वयं को गौरवान्वित मानता हूँ।

हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, बल्कि संवेदनाओं और सांस्कृतिक एकता की वह सशक्त डोर है जो हमें एक सूत्र में बाँधती है। साथ ही, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रशासनिक और कार्यसंचालन में समुचित प्रयोग हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करना न केवल एक दायित्व है, अपितु यह हमारे कार्य संस्कृति को अधिक सशक्त, सरल और प्रभावी बनाता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि पिछले वर्ष मिधानि को राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नराकास (उ.) द्वारा राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही, हमारी ई-पत्रिका 'संकल्प' को भी उत्तम ई-पत्रिका का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धियाँ हमारी राजभाषा के प्रति प्रतिबद्धता, टीम भावना और सम्मान को दर्शाती हैं। जानकर खुशी हुई कि संकल्प का पिछला अंक 'एक पेड़ माँ के नाम' विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था और अब यह अंक गाँव, शहर और पर्यावरण विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यह विषय हमारे जीवन के परिवेश, प्रकृति और सामाजिक संतुलन की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबके समन्वित प्रयासों से मिधानि राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में नई ऊँचाइयों को छुएगा तथा 'संकल्प' पत्रिका इसी तरह नित नवीनता, गुणवत्ता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ आगे बढ़ती रहेगी।

आइए, हम सभी मिलकर इस 'संकल्प' को एक अभियान बनाएं - भाषा का, संस्कृति का, और मिधानि के सतत विकास का।

जय हिंद!

नारायण मूर्ति

(डॉ. एसवीएस नारायण मूर्ति)

निदेशक (वित्त) का संदेश...

श्री एन गौरी शंकर राव
निदेशक (वित्त)
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
कंचनबाग, हैदराबाद–500 058
फोन नं.–040–24184519
ई–मेल: df@midhani-india.in

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीयता की आत्मा है। यह हमारी परंपराओं, मूल्यों और विविधताओं को जोड़ने वाली वह कड़ी है, जो देश के कोने–कोने को एक सूत्र में बांधती है। इसे भारत संघ की राजभाषा का दर्जा भी मिला हुआ है। अब हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं रही, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली की अहम भाषा भी बन गई है।

मिधानि जैसे तकनीकी संस्थान में भी हिंदी के प्रति सम्मान और उसका प्रयोग निष्ठापूर्वक किया जा रहा है। यह तभी संभव हो पाया है जब संगठन के हर अधिकारी और कर्मचारी ने इसे केवल दायित्व नहीं, बल्कि आत्मीयता से अपनाया है। हिंदी में कार्य करना न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक गौरव को भी जीवंत करता है।

'संकल्प' जैसी गृह पत्रिकाएँ इस दिशा में प्रेरणास्रोत बनती हैं। पत्रिका का हर अंक न केवल जानकारी प्रदान करता है, बल्कि संगठन के भीतर संवाद की हिंदी धारा को भी प्रवाहमान करता है।

इस संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि हम भाषा के साथ-साथ अपने सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों को भी समझें। गाँव और शहर, दोनों ही भारत की आत्मा के दो पहलू हैं–जहाँ एक ओर गाँवों में हमें प्रकृति की सहजता और सादगी मिलती है, वहीं शहरों में प्रगति और तकनीक की गूँज सुनाई देती है। लेकिन दोनों का संतुलन तभी संभव है, जब हम अपने पर्यावरण के प्रति सजग हों। स्वच्छ हवा, साफ जल और हरित परिवेश केवल आवश्यकताएँ नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी हैं। इसलिए, जैसे हम हिंदी को आत्मसात कर रहे हैं, वैसे ही गाँवों की सादगी, शहरों की रफ्तार और पर्यावरण की शुद्धता–इन तीनों को समान रूप से सहेजने की आवश्यकता है। प्रसन्नता का विषय है कि संकल्प के इस नवीनतम अंक के केंद्र में गाँव, शहर और पर्यावरण को रखा गया है।

मैं उन सभी रचनाकारों की प्रशंसा करता हूँ, जिनकी लेखनी ने 'संकल्प' को समृद्ध किया है। साथ ही हिंदी अनुभाग को इस नए अंक के लिए ढेरों शुभकामनाएँ। आइए, हम सब मिलकर हिंदी को भी आगे बढ़ाएं और अपने सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्यों को भी सशक्त बनाएं।

जय हिंद! जय हिंदी!!

गौरीशंकर

श्री एन गौरी शंकर राव

निदेशक (उत्पादन एवं विपणन) का संदेश...

श्री टी. मुत्तुकुमार
निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
कंचनबाग, हैदराबाद–500 058
फोन नं.–040–24184242
ई–मेल: dpm@midhani-india.in

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह वह सूत्र है जो भारत की विविधता में एकता की भावना को जोड़ता है। राजभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका केवल प्रशासनिक तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, सोच और सामाजिक सरोकारों की संवाहिका भी है।

मिधानि में हिंदी को प्रोत्साहन देने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। प्रबंधन द्वारा हिंदी में कार्य को सहज और सम्मानजनक बनाने का माहौल भी सृजित किया गया है।

सृजनात्मक विचारों और रचनात्मक अभिव्यक्तियों को मंच देने वाली मिधानि की गृह पत्रिका 'संकल्प' का नवीनतम अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। इस अंक में विशेष रूप से गाँव, शहर और पर्यावरण से जुड़ी रचनाएँ शामिल की गई हैं। आज जब एक ओर गाँवों का पारंपरिक जीवन धीरे-धीरे शहरी प्रभावों में ढल रहा है, वहीं शहरों को भी अब यह समझ आने लगा है कि सतत विकास का मार्ग केवल तकनीक नहीं, बल्कि प्रकृति और परंपरा के संतुलन से होकर जाता है।

गाँव और शहरों, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है-स्वस्थ पर्यावरण और संवेदनशील सोच। यह आवश्यक है कि विकास की दौड़ में हम हरियाली, स्वच्छ वायु और जल-संरक्षण जैसे मूल प्रश्नों को न भूलें। 'संकल्प' का यह नया अंक इन्हीं विचारों की धरती पर खिला एक पुष्प है, जिसमें विचारों की सुवास है और सामाजिक चेतना की मिठास।

मैं उन सभी रचनाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ जिनकी लेखनी ने इस अंक को विचारशील और समृद्ध बनाया। साथ ही हिंदी अनुभाग को इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

आइए, हम सभी मिलकर 'संकल्प' के माध्यम से हिंदी, पर्यावरण और सामाजिक चेतना को नई दिशा दें।

टी. मुत्तुकुमार

अपर महाप्रबंधक की कलम से...

श्री हरिकृष्ण वी.
अपर महाप्रबंधक (प्रभारी मानव संसाधन)
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
कंचनबाग, हैदराबाद–500 058
फोन नं.–040–24184587
ई–मेल:
harikrishna.v@midhani-india.in

इस समय आप मिधानि की गृह पत्रिका 'संकल्प' का विशेषांक पढ़ रहे हैं। किसी भी संगठन की रचनात्मकता, भाषा प्रेम और सामाजिक सरोकारों का परिचायक उसके साहित्यिक प्रकाशन होते हैं, और मिधानि की 'संकल्प' पत्रिका इस भूमिका को पूर्ण समर्पण और उत्तरदायित्व के साथ निभा रही है।

यह पत्रिका न केवल मिधानि की गतिविधियों को राजभाषा के माध्यम से सभी कर्मचारियों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है, बल्कि यह हमारे कर्मचारियों को हिंदी लेखन की ओर प्रेरित करने वाला एक प्रभावशाली मंच भी है। इस मंच के माध्यम से अनेक प्रतिभाशाली अधिकारी और कर्मचारी अपने विचारों, अनुभवों और कल्पनाओं को साझा करते हैं-कभी कविता के रूप में, तो कभी लघु कथा या लेख के माध्यम से।

इस बार 'संकल्प' का विशेषांक 'गाँव, शहर और पर्यावरण' जैसे सामयिक और विचारोत्तेजक विषय को समर्पित है। आज के समय में जब शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है और गाँव धीरे-धीरे अपनी परंपरागत पहचान से दूर होते जा रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखें।

गाँव, जहाँ अभी भी प्रकृति की आत्मा जीवित है, वहीं शहरों में तकनीकी उन्नति और सुविधाओं का जाल फैला है। लेकिन यह विकास तभी सार्थक है जब वह पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी हो। स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और हरित परिवेश-ये सब न केवल गाँव की धरोहर हैं, बल्कि शहरों की ज़रूरत भी बन चुकी हैं।

इस विशेषांक में प्रकाशित रचनाएँ इस त्रिकोण-गाँव, शहर और पर्यावरण-के विविध पहलुओं को उजागर करती हैं और हमें सोचने पर विवश करती हैं कि हम प्रकृति, परंपरा और प्रगति के बीच कैसा संतुलन बना रहे हैं।

मिधानि द्वारा हिंदी भाषा के प्रशिक्षण, टंकण अभ्यास, तथा हिंदी दिवस व विश्व हिंदी दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति जो उत्साह जगाया गया है, वह इस पत्रिका की सामग्री में स्पष्ट परिलक्षित होता है।

'संकल्प' के इस विशेषांक में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और हिंदी अनुभाग को निरंतर प्रयासों व समर्पण के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

आशा है कि यह अंक न केवल पठनीय होगा, बल्कि हमारी संवेदनशीलता, भाषा प्रेम और पर्यावरणीय चेतना को भी जाग्रत करेगा।

हरिकृष्ण वी.

MIDHANI

'गाँव, शहर और प्रदूषण' विशेषांक

यह विशेषांक 'गाँव, शहर और प्रदूषण' जैसे समसामयिक विषय पर पर्यावरणीय और सामाजिक संबंधों पर गंभीर विचार का अवसर प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि मिधानि की ई-पत्रिका का पूर्ववर्ती अंक 'एक पेड़ माँ के नाम' विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसे पाठकों से सराहनीय प्रतिसाद मिला। प्रस्तुत अंक उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है, और इसे आप तक पहुँचाते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और उससे उत्पन्न प्रदूषण ने गाँवों के अस्तित्व पर गंभीर प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है। यह न केवल पर्यावरणीय बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक गहन चिंता का विषय है। आज, जब हमारे मानस में शहरी सोच गहराई से बस चुकी है, तब भी हमारे भीतर कहीं न कहीं गाँव जीवित है। यही कारण है कि तीज-त्योहारों पर, छुट्टियों में, हमारा मन अनायास ही उन कस्बों, देहातों और गाँवों की ओर दौड़ पड़ता है जहाँ हमारे पूर्वजों की स्मृतियाँ बसती हैं।

गाँव केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षक है। इसकी परंपराएँ, बोली-बानी और जीवनशैली हमारी अस्मिता की पहचान हैं। गाँव जीवित रहेगा, तभी हमारी परंपराएँ, हमारी भाषा और हमारी सांस्कृतिक विविधता जीवित रह पाएगी। ग्रामीण बोली से उपजी पहचान को कोई मिटा नहीं सकता और हमें इसे मिटने भी नहीं देना चाहिए।

इसी क्रम में, हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के संरक्षण की आवश्यकता भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। आज, जब हम संवाद के युग में जी रहे हैं, भाषा की भूमिका और अधिक केंद्रीय हो गई है। हिंदी केवल हमारी राजभाषा नहीं, बल्कि वह सेतु है जो देश की आत्मा से हमें जोड़ता है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में इसका प्रयोग लगातार सशक्त हो रहा है।

परंतु यह भी सत्य है कि तकनीकी उन्नति के साथ-साथ हम भाषाई चेतना से दूर होते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम हिंदी और उसकी विविध बोलियों के संरक्षण और संवर्धन को अपना संकल्प बनाएं और इसे अपनी पहचान का अभिन्न अंग बनाएं।

संकल्प के 'गाँव, शहर और प्रदूषण' विशेषांक को साकार रूप प्रदान करने में मदद करने वाले संपादन मंडल के सहयोगियों और लेखकों के प्रति आभारी हूँ। आशा है, पाठक वर्ग इस अंक को भी पसंद करेगा। अस्तु।

(डॉ. बी. बालाजी)

मिधानि ने किया नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक उपक्रम), हैदराबाद–सिकंदराबाद की 60वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन

डॉ. एस के झा, सीएमडी, मिधानि, नराकास (उ.) अध्यक्ष श्री अनुराग कुमार, सीएमडी, ईसीआईएल, उप निदेशक (कार्या.), बेंगलूरु श्री अनिर्बान बिश्वास के साथ मिधानि के राजभाषा कार्यान्वयन तथा राजभाषा कार्यकारिणी समिति के सदस्य

11 नवम्बर 2024 को मिधानि के उत्कृष्टता केंद्र भवन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक उपक्रम), हैदराबाद–सिकंदराबाद की 60वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा टोलिक (सार्व. उप.) के अध्यक्ष श्री अनुराग कुमार ने की। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मिधानि के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (तत्कालीन) डॉ. एस के झा ने विशेष अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की।

अध्यक्षीय संबोधन :

बैठक का आरंभ नराकास (सार्वजनिक उपक्रम) के अध्यक्ष एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अनुराग कुमार ने उपस्थित सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों, राजभाषा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी सदस्य कार्यालयों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है, बल्कि यह कार्यालयीन संवाद का एक सशक्त माध्यम भी बन सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा क्रियान्वयन में सभी आवश्यक संसाधनों और प्रशिक्षणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे हिंदी को और अधिक व्यावसायिक एवं प्रभावशाली बनाया जा सके। इसके लिए नवीनतम तकनीकी सॉफ्टवेयरों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।

श्री अनुराग कुमार ने अपने संबोधन में सभी पुरस्कार विजेताओं एवं सदस्य कार्यालयों को बधाई दी। अंत में उन्होंने यह भी जोड़ा कि हिंदी का प्रयोग देश की एकता, सांस्कृतिक विविधता और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

विशेष अतिथि का संबोधन :

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. संजय कुमार झा ने बैठक के आयोजन को मिधानि के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने ईसीआईएल द्वारा इस बैठक को उत्कृष्ट तरीके से आयोजित करने के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बैठकों से न केवल राजभाषा क्रियान्वयन की दिशा में ठोस उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, बल्कि सदस्य कार्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय की भावना भी

नराकास (उ.) की 60वीं बैठक की झलकियाँ

दीप प्रज्ज्वलन-डॉ. एस के झा, सीएमडी (तत्कालीन), मिधानि, नराकास (उ.) अध्यक्ष श्री अनुराग कुमार, सीएमडी, ईसीआईएल, उप निदेशक (कार्या.) श्री अनिर्बान बिश्वास

ई-पत्रिका वर्ग के अंतर्गत मिधानि को राजभाषा गृह पत्रिका संकल्प को उत्तम पत्रिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया

बीईएल तथा एचएएल की राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अधिकारीगण

नराकास (उ.) अध्यक्ष श्री अनुराग कुमार, सीएमडी, ईसीआईएल को मिधानि की ओर से स्मृति चिह्न भेंट किया गया

हिंदी भाषा के महत्व पर गीत प्रस्तुत करते हुए बीपीडीएवी के छात्र

नराकास (उ.) की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिधानि के कर्मचारीगण सम्मानित

श्रीमती मनाली हिंगरजिया, प्रबंधक (आईटी), मिधानि शब्दावली प्रतियोगिता का द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्रीमती गरिमा ओझा, सहा. प्रबंधक (वित्त), मिधानि वाक् प्रतियोगिता का प्रथम (हिंदी भाषी) पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्रीमती उदया चंद्रिका, वरि. प्रबंधक (एचआरएम), मिधानि वाक् प्रतियोगिता का प्रथम (अन्य भाषी) तथा पीपीटी का तृतीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री दीपक पार्थसारथी, प्रबंधक (मा.संसा.), मिधानि सुलेख व श्रुतिलेख प्रतियोगिता का तृतीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए मिधानि के श्री ईश्वर प्रसाद, प्रबंधक (डब्ल्यूपीएम) और श्री राजकुमार साहू, तकनीशीयन

श्री आदि नारायणा, वरि. कार्या.अधी, गुणता विभाग, मिधानि टंकण प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए

प्रबल होती है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि हमारे तकनीकी उत्पादों, जो विदेशों को भी भेजे जाते हैं, उनमें यथासंभव हिंदी का उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने राजभाषा के प्रचार–प्रसार में ईसीआईएल के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

उप निदेशक (कार्यान्वयन) के विचार :

आधिकारिक भाषा विभाग, दक्षिण क्षेत्र के उपनिदेशक श्री अनिर्बान कुमार विश्वास ने बैठक में सदस्य कार्यालयों की राजभाषा संबंधी प्रस्तुतियों और छमाही रिपोर्टों का अवलोकन करते हुए समिति के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद–सिकंदराबाद क्षेत्र की टोलिक (सार्व. उप.) द्वारा किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं।

उन्होंने राजभाषा अधिनियम, नियमों, कार्यालयीन पत्राचार एवं संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण से संबंधित प्रश्नावली भरने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने 'कंठस्थ 2.0' नामक अनुवाद सॉफ़्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने का सुझाव देते हुए इसे सभी कर्मचारियों द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

अन्य प्रमुख गतिविधियाँ :

राजभाषा कार्यान्वयन प्रस्तुतियाँ :

बैठक में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) एवं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा राजभाषा क्रियान्वयन पर प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ दी गईं। बीईएल की प्रस्तुति श्री सुरेश कुमार, उप प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा की गई जबकि एचएएल की प्रस्तुति डॉ. प्रत्युषा, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा दी गई।

सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार :

ई–पत्रिका श्रेणी में मिधानि की 'संकल्प' एवं एनएमडीसी की 'खनिज भारती' पत्रिकाओं को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। संपादकीय टीमों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

गृह पत्रिका 'पथिक' का विमोचन :

मिधानि और नराकास के अध्यक्षों द्वारा गृह पत्रिका 'पथिक' के 21वें डिजिटल अंक का विमोचन किया गया। सभी सदस्य कार्यालयों को यह अंक ई–मेल के माध्यम से भेजा गया। अध्यक्ष ने लेखकों को बधाई देते हुए आगे भी इसी प्रकार सृजनशील लेखन हेतु प्रेरित किया।

पुरस्कार वितरण एवं सम्मान :

बैठक के अंतिम चरण में वर्ष 2024 के दौरान आयोजित विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही, सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने से उत्पन्न धुआं है।यह लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है, जैसे कि WHO (https://www.who.int/) के अनुसार हर साल लाखों लोगों की समयपूर्व मृत्यु होती है। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए NCAP (2019) और BS-VI मानक जैसे उपाय शुरू किए हैं (स्रोत: https://www.moef.gov.in/)।

IQAir (https://www.iqair.com) की 2023 रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है।

राजभाषा हिंदी के संवर्धन
हेतु कार्यशालाओं का आयोजन

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) द्वारा अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में राजभाषा हिंदी के सशक्त अनुप्रयोग और प्रचार–प्रसार हेतु पत्रिका प्रकाशन अवधि (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025) के दौरान क्रमश: 14.11.204, 18.04.2025 और 06.02.2025 को तीन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ये कार्यशालाएँ कर्मचारियों को राजभाषा नीति की जानकारी प्रदान करने, हिंदी में दक्षता बढ़ाने और कार्यस्थल पर हिंदी के प्रभावी प्रयोग हेतु मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से आयोजित की गईं।

कार्यशालाओं का उद्देश्य एवं प्रारंभिक जानकारी

प्रत्येक कार्यशाला की शुरुआत मिधानि के हिंदी अनुभाग एवं निगम संचार के प्रबंधक डॉ. बी. बालाजी द्वारा प्रतिभागियों के स्वागत एवं कार्यशाला के उद्देश्यों की व्याख्या से हुई। उन्होंने बताया कि हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को राजभाषा नीति, हिंदी में प्रशासनिक कार्य, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण के उपाय, तकनीकी उपकरणों में हिंदी की उपयोगिता और सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है।

राजभाषा अनुपालन
में कर्मचारियों की भूमिका

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिंदी अधिकारी श्रुति पांडे ने 'राजभाषा नीति के अनुपालन में कर्मचारियों का दायित्व' विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने राजभाषा अधिनियम, 1963 व राजभाषा नियम, 1976 की प्रमुख धाराओं की व्याख्या करते हुए बताया कि कर्मचारी का सहयोग राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अत्यावश्यक है। उन्होंने कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ एक नमूना राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन भी किया, जिससे प्रतिभागियों को समिति की कार्यप्रणाली की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हुई।

राजभाषा में सरकारी कार्य और जिम्मेदारियाँ

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के हिंदी अधिकारी श्री रवि रंजन ने 'राजभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका और कर्मचारियों का दायित्व' विषय पर व्याख्यान देते हुए बताया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने में कर्मचारियों की सक्रियता की आवश्यकता है। उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन के प्रमुख छह हितधारकों – केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, कार्यालय व कर्मचारी, संसदीय राजभाषा समिति, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, संबंधित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ, हिंदी से जुड़ी स्वैच्छिक संस्थाएँ की चर्चा करते हुए रेखांकित किया कि इन्हीं छह हितधारकों की कार्य प्रणाली और योजनाओं से राजभाषा कार्यान्वयन को गति मिलती रहती है। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने दैनिक कार्यों में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करें और विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दें।

सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी की भूमिका

दक्षिण मध्य रेलवे की वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी डॉ. रानी गीतेश काटे ने 'राजभाषा कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर व्याख्यान देते हुए बताया कि हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अपनी वैज्ञानिकता के कारण तकनीकी यंत्रों और कंप्यूटर में सहजता से प्रयुक्त की जा सकती है।

उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण के लिए कूंजी पटल चयन, स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक और गूगल फॉर्म पर हिंदी में टंकण जैसे उपकरणों का कैसे उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, हिंदी शब्द सिंधु ई-महा शब्दकोश, कंठस्थ अनुवाद पोर्टल, और ई-सरल हिंदी वाक्य कोश जैसे ऑनलाइन संसाधनों की जानकारी दी।

प्रशासनिक शब्दावली का अभ्यास

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहायक निदेशक (से.नि.) मु. कमालुद्दीन ने 'कार्यालयीन कामकाज में प्रयुक्त प्रशासनिक शब्दावली' विषय पर जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशासनिक शब्दों की उत्पत्ति, गठन प्रक्रिया और विभिन्न संदर्भों में उनके प्रयोग के बारे में रोचक व उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को शब्दावली के सटीक प्रयोग का अभ्यास भी कराया, जिससे उन्हें अपने दैनंदिन कार्य में हिंदी का प्रयोग आत्मविश्वासपूर्वक करने की प्रेरणा मिली।

इन कार्यशाला के सफल आयोजन में हिंदी विभाग की कनिष्ठ कार्यपालक (एनयूएस) श्रीमती डी. वी. रत्नाकुमारी, तथा डाक अनुभाग के संविदाकर्मी श्री जयपाल एवं श्री नरेंद्र गांधी का विशेष योगदान रहा। कार्यशालाओं का समापन प्रतिभागियों द्वारा राजभाषा हिंदी में कार्य करने की सामूहिक शपथ के साथ किया गया।

राजभाषा शपथ

मैं, शपथ लेता / लेती हूँ कि राजभाषा के रूप में संविधान द्वारा स्वीकृत हिंदी का अपने कामकाज में उपयोग करूंगा / करूंगी। टिप्पणी व पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य अपने स्तर पर हासिल करूंगा / करूंगी। राजभाषा के प्रसार-प्रचार के लिए प्रबंधन द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों में सहयोग करूंगा / करूंगी ।

जय हिंद, जय हिंदी !!!

हरियाली की ओर बढ़ते कदम: मिधानि का पर्यावरण संरक्षण में योगदान

आवरण कथा

साई बाबू
सहायक प्रबंधक (ईएमएस)

आज का युग औद्योगिक प्रगति का युग है, लेकिन इस प्रगति की एक बड़ी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। प्रदूषण, संसाधनों की अत्यधिक खपत, जैव विविधता का ह्रास और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ दिन–ब–दिन गंभीर होती जा रही हैं। ऐसे में यदि कोई औद्योगिक इकाई उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए कार्य करती है, तो वह एक प्रेरक उदाहरण बन जाती है। मिधानि (मिश्र धातु निगम लिमिटेड) ने यही आदर्श प्रस्तुत किया है।

भारत सरकार के अधीन यह प्रतिष्ठान न केवल विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं के निर्माण में अग्रणी है, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी अपने संगठनात्मक संस्कृति में समाहित कर चुका है। आइए, मिधानि द्वारा किए जा रहे कुछ पर्यावरण–संवेदनशील कार्यों पर एक दृष्टि डालते हैं:

1. पौधारोपण: 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत 12,144 पौधों का रोपण

मिधानि ने 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसी भावनात्मक और जागरूकता फैलाने वाली पहल के तहत 12,144 पेड़ों का रोपण कर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय प्रयास नहीं, बल्कि मातृत्व और प्रकृति के बीच के संबंधों को भी उजागर करता है। प्रत्येक लगाए गए पेड़ को माँ के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में देखा गया, जिससे इसमें भागीदारी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का भावनात्मक जुड़ाव और भी प्रगाढ़ हुआ।

2. प्राकृतिक खाद का उपयोग: जैविक दृष्टिकोण की ओर एक कदम

रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जहाँ मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं मिधानि ने इसका विकल्प चुना – प्राकृतिक खाद। जैविक अपशिष्ट, पत्तियाँ, रसोई से उत्पन्न कचरा, आदि को खाद में परिवर्तित कर मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा रहा है। इससे परिसर की हरियाली भी पोषित होती है और अपशिष्ट का पुन: उपयोग भी सुनिश्चित होता है।

3. ड्रिप इरिगेशन प्रणाली: जल की बचत में तकनीक का उपयोग

पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों में जल की भारी बर्बादी होती है। मिधानि ने इसे समझते हुए अपने उद्यानों और पौधारोपण क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन प्रणाली को अपनाया है। इस प्रणाली में पौधों की जड़ों तक सीधे जल पहुंचता है, जिससे जल की खपत में 30–40% तक कमी आती है। यह प्रणाली आधुनिक, कुशल और पर्यावरण हितैषी है।

4. जल संरक्षण: जलाशयों का रखरखाव और वर्षा जल संचयन

जल संरक्षण आज के युग की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है।

मिधानि ने इसके लिए दोहरे उपाय अपनाए हैं – जलाशयों की नियमित सफाई और देखरेख, तथा वर्षा जल संचयन की पद्धति (Rain Harvesting Pits)। परिसर में बनाए गए रेन हार्वेस्टिंग पिट्स वर्षा के जल को भूमिगत भंडारण में संचित करते हैं, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है और वर्षा जल व्यर्थ नहीं बहता।

5. हरियाली का जाल: संयंत्र, कार्यालय एवं टाउनशिप में भरपूर वृक्षारोपण

मिधानि का संपूर्ण परिसर हरियाली से आच्छादित है। संयंत्र परिसर, प्रशासनिक भवन, कार्यालय और आवासीय टाउनशिप में सघन वृक्षारोपण किया गया है। इन वृक्षों में पीपल, आम, नीम, बबूल, सागौन (टेक), बादाम, पाम, नारियल और गुलमोहर जैसे वृक्ष शामिल हैं। ये न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि गर्मी में छाया प्रदान कर तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। ये वृक्ष जैव विविधता के लिए भी आश्रय प्रदान करते हैं।

6. लॉन का रखरखाव : 92,000 वर्गफुट का हरित क्षेत्र

मिधानि परिसर में 92,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में फैला लॉन अत्यंत आकर्षक और स्वच्छ है। इस हरित क्षेत्र की नियमित देखभाल, सिंचाई और सौंदर्यीकरण किया जाता है, जिससे कर्मचारियों और आगंतुकों को एक शांत, स्वच्छ और ऊर्जा से भरपूर वातावरण मिलता है।

7. नालियों और सीवरेज की सफाई

संयंत्र और टाउनशिप की नालियों और सीवरेज प्रणाली का नियमित रूप से सफाई कार्य किया जाता है। इससे जल–जमाव, बदबू और मच्छरों की उत्पत्ति जैसी समस्याएँ नहीं होतीं। यह प्रयास स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है।

8. सौर ऊर्जा : 4 मेगावाट संयंत्र और 60 किलोवॉट पीक रूफटॉप सिस्टम

मिधानि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में भी अग्रणी है। 4 मेगावाट क्षमता वाला ग्राउंड सोलर प्लांट और 60 किलोवॉट पीक रूफटॉप सोलर सिस्टम मिलकर प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करते हैं। इससे पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता कम होती है और कार्बन उत्सर्जन में भी भारी गिरावट आती है।

9. कचरा प्रबंधन : अपशिष्ट से उपयोगी संसाधन की ओर

मिधानि सभी प्रकार के अपशिष्ट-औद्योगिक, जैविक, ई–वेस्ट और खतरनाक कचरे का उचित और पृथक्कृत निपटान सुनिश्चित करती है। कैंटीन और रसोईघर से निकलने वाले जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए विशेष गड्ढे बनाए गए हैं। इससे 'कचरे से संपदा' (Waste to Wealth) का आदर्श साकार होता है।

10. मोर अभयारण्य : एक अनूठा संरक्षण स्थल

मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और मिधानि परिसर में इसे संरक्षित करने हेतु विशेष मोर अभयारण्य स्थापित किया गया है। यह अभयारण्य परिसर की जैव विविधता को समृद्ध करता है और कर्मचारियों के लिए एक प्राकृतिक, सजीव वातावरण प्रदान करता है।

11. कागजरहित कार्य प्रणाली : ई–ऑफिस की दिशा में पहल

मिधानि ने कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप देकर कागज की खपत में कमी लाई है। कार्यालय में ई–फाइलिंग, डिजिटल दस्तावेजीकरण, और पेपरलेस संप्रेषण को बढ़ावा दिया गया है, जिससे वन संसाधनों की रक्षा होती है।

12. जागरूकता कार्यक्रम : प्रशिक्षण, स्वच्छता पखवाड़ा, स्वास्थ्य शिविर

मिधानि पर्यावरण संरक्षण की जानकारी केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रखती, बल्कि जनजागरूकता को भी प्राथमिकता देती है। स्वच्छता पखवाड़ों, पर्यावरणीय सेमिनारों, और मेडिकल चेकअप कैंप के माध्यम से कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय को जागरूक किया जाता है।

13. समर्पित ईएमएस और यूटिलिटी टीम

मिधानि में संपदा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) और यूटिलिटी संचालन के लिए समर्पित विशेषज्ञों की टीम कार्यरत है, जो सतत निगरानी, रिकॉर्ड–कीपिंग, और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

14. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और हाइड्रोजन प्लांट

संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शोधित करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है, जिससे जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोजन प्लांट स्थापित कर भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए हरित विकल्प विकसित किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष : विकास और संरक्षण का संतुलित संगम

मिधानि का यह व्यापक पर्यावरणीय दृष्टिकोण दर्शाता है कि एक औद्योगिक इकाई भी विकास और संरक्षण दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है। इन पहलों के माध्यम से मिधानि केवल एक धातु उद्योग नहीं रह गया है, बल्कि एक हरित प्रेरणा बनकर उभर रहा है।

यह समय है जब अन्य औद्योगिक इकाइयाँ भी मिधानि से प्रेरणा लेकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाएँ, ताकि भावी पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरा–भरा भविष्य मिल सके।

ग्रामीण जीवन बनाम शहरी जीवन

शुभम कुमार
कनिष्ठ तकनीशियन II

प्रस्तावना :

शहरीकरण की प्रक्रिया ने आज के युग में व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाए हैं। भारत में ग्रामीण जीवन का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की नींव है, जहाँ अधिकांश लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र एक तरह से पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक मूल्यों का संरक्षक है। ग्रामीण जीवन में आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सहयोग की भावना मजबूत होती है, जो सामाजिक स्थिरता को बनाए रखती है।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण जीवन न केवल कृषि उत्पादन में योगदान करता है बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा में भी अपना योगदान देता है। इसीलिए ग्रामीण जीवन का विकास देश की समृद्धि और स्थिरता के लिए अति आवश्यक है। ग्रामीण जीवन पर शहरी जीवन का व्यापक प्रभाव पड़ा है जोकि कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है ताकि विकास के विभिन्न पहलूओं को संतुलित किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों को भी समान अवसर मिल सकें। वैसे ग्रामीण जीवन पर शहरी जीवन का प्रभाव निम्न रूप से देखा जा सकता है:

आर्थिक प्रभाव :

शहरी क्षेत्रों में उद्योग सेवाएं और व्यापार के अवसर अधिक होते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी हो जाती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में निवेश और विकास की अधिक संभावनाएं होती है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास को प्रेरित कर सकती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव :

शहरी जीवन की ओर प्रवासन से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में कमी आ रही है, जिससे पारंपरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी बदलाव आ रहा है। युवा पीढ़ी के शहरों की ओर जाने से गांव में सिर्फ बुजुर्गों की संख्या बच रही है जिससे सामाजिक गतिशीलता प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही शहरी जीवन के साथ आए नए विचार और जीवनशैली ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे–धीरे प्रवेश कर रही है जो ग्रामीणों की पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताओं और रीति–रिवाजों को बदल रही है।

तकनीकी प्रभाव :

शहरी क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी और डिजिटल संरचना की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले अधिक होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति धीमी होती है। हालांकि जैसे–जैसे इंटरनेट और मोबाइल सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है, तकनीकी विभाजन कम होता दिख रहा है।

शरी जीवन से प्रेरित तकनीकी नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनाएं जा रहे हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सुधार ला रहे हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव :

शहरीकरण के साथ संसाधनों का अधिक उपयोग और प्रदूषण बढ़ता है जिससे इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर भी देखा जा सकता है। वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता में भी गिरावट ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर रही है। इससे अतिरिक्त शहरी विस्तार के कारण ग्रामीण लोगों का कृषि के प्रति लगाव घट रहा है जिससे खाद्य उत्पादन और ग्रामीण लोगों का कृषि के प्रति लगाव घट रहा है जिससे खाद्य उत्पादन और ग्रामीण जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि शहरी निवासियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की ओर बढाए गए प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

ग्रामीण आबादी का घटाव :

शहरी जीवन की ओर लोगों के पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जनसंख्या में निरंतर कमी हो रही है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कामकाजी उम्र के लोग हैं उनमें भी निरंतर कमी देखने को मिल रही है, जो कृषि एवं अन्य ग्रामीण कार्यों को निरंतर प्रभावित कर रही है।

ग्रामीणों के शहरों की ओर आकर्षित होने से कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। इसके साथ ही ग्रामीण समाज की दिनचर्या में काफी परिवर्तन हो रहा है।

शिक्षा पर प्रभाव :

शहरों में शिक्षा अधिक उन्नत और सुलभ होती है। बेहतर स्कूल–कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में अधिक होती है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के सुधार के लिए लोगों का ध्यान बहुत कम आकर्षित हो रहा है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव :

शहरों की स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उन्नत है। स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं शहरों में उपलब्ध है जो ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्रामीण बेहतर चिकित्सा के लिए भी गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब वैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं से गांवों की चिकित्सा सुविधा बेहतर हुई है।

कोरोना काल के यदि आंकड़े निकाले जाएं तो पता चलता है कि गांव में लोग शहरों से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड के समय अच्छी चिकित्सा व्यवस्था थी।

सामाजिक असमानताएं :

आज के दिन जो व्यक्ति शहरों से पुन: ग्रामीण समाज में आकर बस रहे हैं वहाँ सामाजिक असमानताएं बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। सामाजिक असमानताएं परिणाम की समानता की कमी को दर्शाती है।

जो व्यक्ति जितना सुविधासंपन्न है वह गरीब को उतना ही दबा रहा है, जो ग्रामीण जीवन पर शहरी जीवन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सामाजिक असमानता आर्थिक असमानता से जुड़ी है। सामाजिक असमानता इतनी देखी जा रही है कि शहरों से आया व्यक्ति किसी भी अपने से नीचे व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं देना चाहता है।

निष्कर्ष :

शहरीकरण का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर व्यापक और जटिल तरीके से हो रहा है। इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े पहलू भी शामिल है। इस स्थिति को समझना और इसका समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है ताकि ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण स्थापित किया जा सके।

हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि शहरीकरण के प्रभाव को सही तरीके से समझा जाए और दोनों प्रकार के जीवन को समान रूप से सम्मानित किया जाए। इससे हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों जीवन एक साथ मिलकर एक अच्छे और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकें। इस कदम के बल पर हम एक अच्छे समाज ही नहीं बल्कि अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण कर सकते हैं।

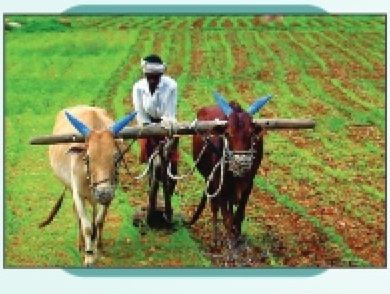

कृषि अब लाभकारी व्यवसाय नहीं रह गई है। भूमि की जोतें छोटी होती जा रही हैं और उत्पादन लागत बढ़ रही है, जिससे किसान और उनके परिवार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति ग्रामीण युवाओं में अधिक देखी जा रही है, जो बेहतर रोजगार और जीवनशैली की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं।

https://www.hindisamay.com/content/10797/ लेखक–अमित–कुमार–विश्वास–की–लेख–बढ़ती–आकांक्षाएँ–और–सिमटता–बचपन.cspx?utm_source

शहरीकरण और ग्रामीण जीवन : एक हरित संतुलन की ओर

धर्मेंद्र कुमार
तकनीकी सहायक
वाइड प्लेट मिल

प्रस्तावना

आज का युग प्रगति और परिवर्तन का है, और शहरीकरण इस परिवर्तन का प्रमुख वाहक बन चुका है। एक ओर यह आधुनिक जीवनशैली, रोजगार और सुविधाओं का द्वार खोलता है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरणीय संतुलन को गहराई से प्रभावित करता है। विशेषकर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, शहरीकरण के प्रभाव केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

यह लेख ग्रामीण जीवन पर शहरीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए यह जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार हम विकास की इस धारा को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए एक हरित भविष्य की ओर मोड़ सकते हैं।

शहरीकरण दो धारी तलवार

शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घटती है, कृषि भूमि का उपयोग बदलता है, और पारंपरिक जीवनशैली धीरे–धीरे लुप्त होती जाती है।

इस प्रक्रिया के केंद्र में है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जो न केवल ग्रामीण जीवन को अस्थिर करता है, बल्कि पर्यावरण को भी दीर्घकालिक क्षति पहुँचाता है।

सामाजिक प्रभाव : सामूहिक जीवन से अलगाव की ओर

1. **संयुक्त परिवारों का विघटन** : पहले जहाँ एक साथ खेती, वृक्षारोपण और जल संरक्षण होता था, आज एकल परिवारों में यह सामूहिक चेतना खोती जा रही है।
2. **शहरी संस्कृति का प्रवेश** : ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी खानपान, फैशन, और उपभोगवादी प्रवृत्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं, जिससे पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली धीरे–धीरे खत्म हो रही है।
3. **शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर** : इन क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रवेश ने निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, जो सकारात्मक पहलू है, लेकिन यह केवल भौतिक विकास तक सीमित रहा है, जबकि पर्यावरणीय शिक्षा की अभी भी भारी कमी है।

आर्थिक प्रभाव : कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर संकट

1. **कृषि भूमि का क्षरण** : शहरीकरण के विस्तार के लिए कृषि भूमि को आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग में लाया जा रहा है। इससे उत्पादन क्षमता घटती है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है।
2. **स्थानीय उद्योगों की उपेक्षा** : हस्तशिल्प, बांस उद्योग, और जैविक उत्पाद आधारित रोजगार के साधन शहरीकरण की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं, जबकि यही उद्योग पर्यावरण मित्र होते हैं।
3. **रोज़गार का असंतुलन** : युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे न केवल श्रमशक्ति का अभाव हो रहा है, बल्कि गांवों में हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण की संभावना भी कमजोर हो रही है।

सांस्कृतिक प्रभाव : रीति–रिवाजों से दूर होती प्रकृति

1. **परंपराएं जो पर्यावरण सहेजती थीं** : ग्रामीण जीवन के अनेक रीति–रिवाज जैसे वनों की पूजा, फसल उत्सव, जलस्रोतों की पूजा आदि पर्यावरण संरक्षण के सहज साधन थे।
2. **स्थानीय बोलियों और परिधानों का लोप** : पर्यावरण के अनुसार ढले हुए पारंपरिक परिधान और भाषाएँ धीरे–धीरे विलुप्त हो रही हैं, जो हमारी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का हिस्सा थीं।
3. **भोजन में बदलाव** : पारंपरिक पौष्टिक और स्थानीय खाद्य पदार्थों की जगह फास्ट फूड और पैकेज्ड खाद्य सामग्री ने ले

ली है, जिससे न केवल स्वास्थ्य पर, बल्कि स्थानीय जैव विविधता पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।

पर्यावरणीय प्रभाव : प्रकृति पर प्रगति की भारी कीमत

1. **भूमि उपयोग में परिवर्तन:** शहरीकरण के चलते कृषि योग्य भूमि पर भवन, सड़क और कारखाने बनाए जा रहे हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन की क्षमता और हरियाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. **प्रदूषण का विस्तार:** शहरी अपशिष्ट, प्लास्टिक और औद्योगिक प्रदूषण अब गांवों तक पहुँच चुका है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

3. **जैव विविधता का संकट :** वनों की कटाई, ग्रीन बेल्ट्स का क्षरण, और जलाशयों का शहरी उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की जैव विविधता को समाप्त कर रहा है। इससे पक्षियों, कीटों और जानवरों की प्रजातियाँ संकट में हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनिवार्य हैं।

समाधान : विकास और संरक्षण का संतुलन

1. **हरित ग्राम योजना:** प्रत्येक गाँव को एक मॉडल पर्यावरणीय गाँव के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा, जैविक खेती और कचरा प्रबंधन अनिवार्य हों।

2. **स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करें:** बांस, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और ग्रामीण पर्यटन जैसे उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साधा जा सकता है।

3. **कौशल और पर्यावरणीय शिक्षा:** ग्रामीण युवाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि विषयों में प्रशिक्षित किया जाए।

4. **नीति निर्माण में ग्रामीण भागीदारी :** पर्यावरणीय योजनाएँ बनाते समय स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि समाधान स्थानीय ज़रूरतों और पारिस्थितिक सच्चाइयों के अनुकूल हों।

5. **सतत आवास और निर्माण:** ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, स्कूलों और संस्थानों का निर्माण स्थानीय सामग्री से और ऊर्जा दक्ष तरीके से किया जाए।

निष्कर्ष

शहरीकरण एक आवश्यकता है, लेकिन यदि यह बिना पर्यावरणीय समझ और ग्रामीण संतुलन के बढ़े, तो यह हमारे समाज को विनाश की ओर ले जा सकता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति और प्रगति एक–दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहचर हो सकते हैं – बशर्ते हम अपने विकास के मार्ग को हरित सोच से संचालित करें।

अब समय आ गया है कि हम शहरीकरण को केवल कंक्रीट और तकनीक की दृष्टि से न देखें, बल्कि उसे एक ऐसे अवसर के रूप में समझें, जहाँ ग्रामीण जीवन, पारंपरिक ज्ञान, और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक संतुलित, समृद्ध और हरित भविष्य की ओर बढ़ा जा सके।

भारत में प्लास्टिक कचरा एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुका है। हालिया अध्ययनों के अनुसार, भारत विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, जो वैश्विक प्लास्टिक कचरे का लगभग 20% उत्पन्न करता है।

(https://www.plasticsforchange.org/blog/india-emerges-as-the-worlds-largest-plastic-polluter-what-went-wrong-and-whats-next?utm_source)

प्रकृति की पुकार : गाँव, शहर और पर्यावरणीय संतुलन की खोज

रोहित बाखला
वरिष्ठ तकनीकी सहायक
आई.सी.पी.

कहते हैं समय कभी एक–सा नहीं रहता। ठबदलाव ही संसार का नियम हैठ–यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहराई लिए होती है। समय, समाज, तकनीक और मानव जीवन के साथ–साथ हमारा पर्यावरण भी निरंतर परिवर्तन की राह पर है। यह बदलाव कभी हमारे जीवन को सहज बनाता है, तो कभी संकट की ओर धकेलता है। मैंने अपने जीवन में गाँव की हरियाली से लेकर शहर की चकाचौंध तक, और प्राकृतिक संतुलन से लेकर पर्यावरणीय संकट तक-हर बदलाव को करीब से देखा है।

गाँव की मिट्टी, जीवन की सादगी

मेरा नाम रोहित है, और मैं झारखंड के एक छोटे से गाँव शॉची का निवासी हूँ। मेरा बचपन खेतों, पेड़ों, नदियों और पक्षियों की चहचहाहट के बीच बीता। वहाँ बिजली की कमी थी, पक्की सड़कें नहीं थीं, लेकिन जीवन में संतुलन था, सामंजस्य था और प्रकृति से जुड़ाव था। हमारे परिवार की आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर थी। अच्छे मौसम में फसलें लहलहाती थीं और पूरा गाँव खुशी से झूम उठता था। लेकिन जब वर्षा कम होती या बेमौसम तूफान आता, तो दुख और चिंता की लहर फैल जाती।

गाँव का जीवन भले ही सुविधाओं के अभाव में था, लेकिन वहाँ शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और जैव विविधता से भरपूर वातावरण था। हम जानते थे कि अगर हमें जीवित रहना है, तो हमें प्रकृति की लय के साथ चलना होगा। तब ठपर्यावरण संरक्षणठ कोई अभियान नहीं था, वह जीवन का हिस्सा था। खेतों में बिना रासायनिक खाद के खेती होती, पशुपालन जैविक रूप से होता, और नदियाँ साफ रहतीं।

शहर की ओर कदम, प्रदूषण की ओर दृष्टि

समय के साथ, जैसे-जैसे शिक्षा पूरी हुई, मैंने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया और 2020 में नौकरी की तलाश में हैदराबाद शहर आ गया। यह पहला अवसर था जब मैंने गाँव को छोड़कर किसी बड़े शहर का रुख किया। वहाँ की ऊँची इमारतें, चमचमाती सड़कें और तकनीकी विकास ने मुझे चकित किया, लेकिन साथ ही मैं वहाँ के पर्यावरणीय संकट से भी रूबरू हुआ।

वहाँ दिन-रात चलता ट्रैफिक, गाड़ियों का धुआँ, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता प्रदूषण, कचरे से भरी नालियाँ और लगातार कम होती हरियाली ने मुझे विचलित कर दिया। मैंने महसूस किया कि शहरीकरण की इस दौड़ में हमने विकास तो कर लिया, लेकिन उसकी कीमत हमारे पर्यावरण ने चुकाई है। विकास और विनाश के बीच की यह रेखा अब बहुत धुंधली हो चुकी है।

गाँव और शहर : पर्यावरणीय दृष्टिकोण से तुलना

ग्रामीण और शहरी जीवन में अंतर केवल रहन-सहन या सुविधाओं का नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और संरक्षण का भी होता है।

गाँवों में जीवन पर्यावरण के साथ अधिक समरस होता है। वहाँ लोग जल स्रोतों की महत्ता समझते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, और भूमि को माँ मानते हैं। इसके विपरीत, शहरों में सुविधाओं की अधिकता ने मनुष्य को प्रकृति से काट दिया है। हम ए.सी. में रहते हैं, बोतलबंद पानी पीते हैं, और कंक्रीट के जंगलों में कैद होकर जीवन जीते हैं।

शहरों की औद्योगिक गतिविधियाँ, यातायात, निर्माण कार्य और उपभोक्तावादी संस्कृति ने वायु, जल और भूमि-तीनों को प्रदूषित कर दिया है। गाँवों में आज भी कुछ हद तक पर्यावरणीय संतुलन बचा है, लेकिन शहरों का प्रभाव वहाँ भी तेजी से फैल रहा है।

जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण संकट

सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि शहरी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब गाँवों पर भी पड़ रहा है। समय पर वर्षा न होना, गर्मी का असामान्य बढ़ना, और कीट–पतंगों का अत्यधिक प्रकोप अब गाँवों की खेती को बर्बाद कर रहा है। इससे न केवल किसानों की आजीविका संकट में पड़ी है, बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है।

आज जब किसान बारिश की राह देखता है, तो बादल छा कर भी बिना वर्षा के लौट जाते हैं। फसलों के खराब होने से उसकी पीढ़ियों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे में वह शहर की ओर पलायन करता है, जहाँ उसे पर्यावरणीय असहजता के साथ सामाजिक उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है।

विकास बनाम संरक्षण : सही दिशा की तलाश

हम यह नहीं कह सकते कि शहरीकरण पूरी तरह गलत है। जीवन को सरल, प्रभावी और उन्नत बनाने के लिए तकनीक और विकास आवश्यक हैं। लेकिन अगर यह विकास प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके, जैव विविधता को समाप्त करके और मानव–प्रकृति के संबंध को तोड़कर हो रहा है, तो यह आत्मघाती है।

हमें एक ऐसे विकास मॉडल की ज़रूरत है जो 'सतत विकास' (Sustainable Development) की भावना से प्रेरित हो। इसमें उद्योग, ऊर्जा, आवास, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय मापदंडों का ध्यान रखा जाए। शहरों में ग्रीन ज़ोन, सोलर एनर्जी, सार्वजनिक परिवहन, वेस्ट मैनेजमेंट, वृक्षारोपण, और जल संरक्षण जैसे उपायों को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

गाँवों में हरित क्रांति की दूसरी लहर

गाँवों को केवल खाद्यान्न उत्पादन का केंद्र न मानकर उन्हें पर्यावरणीय संरक्षण के मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

सरकार को चाहिए कि वह गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ-जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, इंटरनेट और स्वच्छता व्यवस्था–प्रदान करे, ताकि लोग वहाँ सम्मानजनक जीवन जी सकें और शहरों की ओर पलायन न करें। इसके साथ-साथ सामुदायिक वन प्रबंधन, जैविक खेती, स्थानीय जल स्रोतों का पुनर्जीवन, और हरित ग्राम योजना जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे गाँव आत्मनिर्भर बनेंगे और पर्यावरण के सच्चे रक्षक भी।

शिक्षा और जन-जागरूकता : परिवर्तन की कुंजी

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं होगा। इसके लिए सामूहिक जन-जागरूकता और सहभागिता आवश्यक है। बच्चों को स्कूल स्तर से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। युवाओं को तकनीक के साथ–साथ प्रकृति की उपयोगिता भी समझनी होगी। बुजुर्गों के अनुभव और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी को सौंपना होगा।

अगर हम सब मिलकर छोटे-छोटे कदम भी उठाएँ-जैसे प्लास्टिक का प्रयोग न करना, वर्षा जल संचयन करना, पेड़ लगाना, कचरा सही तरीके से निपटाना-तो बड़ा परिवर्तन संभव है।

एक याद जो हमेशा साथ है

आज मैं भले ही शहर में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा आज भी गाँव की मिट्टी में रची-बसी है। वहाँ की सुबहें, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट होती थी; वह नदी, जिसमें बच्चे नहाते थे; वह खेत, जिसमें हम दौड़ते थे-सब आज भी मेरी स्मृति में जीवित हैं।

मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ किताबों में पढ़ें कि कभी गाँव ऐसे हुआ करते थे जहाँ नदियाँ स्वच्छ थीं, पेड़ घने थे और जीवन शांत था।

निष्कर्ष : अब भी समय है

हमारे पास अब भी समय है कि हम पर्यावरण को प्राथमिकता दें। विकास करें, लेकिन ऐसे कि पृथ्वी की धड़कन थमे नहीं। गाँवों को मजबूत करें, ताकि लोग वहाँ रह सकें, प्रकृति के करीब रह सकें। शहरों को हरा-भरा बनाएं, ताकि वहाँ भी जीवन स्वच्छ और स्वस्थ हो सके। हम सभी को मिलकर यह तय करना है कि हम कैसी धरती आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं-एक प्रदूषित, बंजर और संकटग्रस्त धरती, या एक हरी-भरी, शुद्ध और जीवनदायिनी धरती।

प्रकृति हमें पुकार रही है, क्या हम उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं ?

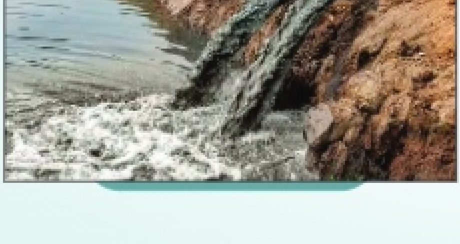

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, भारत में निगरानी की जाने वाली 445 नदियों में से 351 अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रदूषित हैं (सीपीसीबी रिपोर्ट, 2022)।

पर्यावरण और ग्राम्य जीवन : शहरी प्रभाव की चुनौती

शुभम कुमार
उप प्रबंधक, ए.आर.एस.

भारत विविधताओं का देश है—जहाँ एक ओर ग्रामीण जीवन की शांति, सादगी और प्राकृतिक निकटता है, वहीं दूसरी ओर शहरी जीवन की चकाचौंध, तकनीकी उन्नति और तीव्र गतिशीलता है। बीते कुछ दशकों में, शहरीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण भारत पर बहुआयामी प्रभाव डाला है, विशेष रूप से पर्यावरण के संदर्भ में। इस लेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे शहरीकरण के बढ़ते कदमों ने न केवल ग्राम्य संस्कृति को प्रभावित किया है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी एक बड़ा दुष्प्रभाव डाला है।

शहरीकरण और ग्रामीण जीवन का परिवेश

शहरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जनसंख्या गाँवों से शहरों की ओर पलायन करती है, जिससे शहरी क्षेत्र विस्तारित होते हैं और ग्रामीण संसाधन सिकुड़ते जाते हैं। भारत में यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है—परिणामस्वरूप गाँवों की जनसंख्या में गिरावट और शहरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

1. जनसंख्या विस्थापन और पर्यावरणीय बोझ

गाँवों से शहरों की ओर पलायन सिर्फ सामाजिक और आर्थिक संकट ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न करता है। जब शहरों में अत्यधिक जनसंख्या एकत्रित हो जाती है, तो वहाँ के जल, वायु और भूमि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। नए मकानों, सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए हरित भूमि और जंगलों की कटाई होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैलते कंक्रीट जंगलों ने प्राकृतिक हरियाली को लगभग निगल लिया है।

2. संस्कृति और प्रकृति का संतुलन

ग्राम्य संस्कृति सदैव प्रकृति के समीप रही है—चाहे वह त्योहारों का मनाने का तरीका हो या कृषि आधारित जीवनशैली। लेकिन अब शहरी प्रभाव के कारण गाँवों में भी आधुनिकता की दौड़ शुरू हो गई है। डीजे पर होली मनाना, रासायनिक रंगों का प्रयोग, और शोभा यात्राओं में प्लास्टिक की अधिकता ग्राम्य पर्यावरण को नष्ट कर रही है। परंपरागत प्रकृति—संरक्षणकारी पद्धतियाँ धीरे—धीरे विलुप्त हो रही हैं।

3. रोजगार, खेती और पर्यावरणीय असंतुलन

शहरों में अधिक रोजगार अवसरों की लालसा में ग्रामीण युवा गाँवों से पलायन कर रहे हैं। इससे खेती में श्रमिकों की कमी हो रही है और कई बार किसान मशीनीकरण की ओर झुक जाते हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हानिकारक सिद्ध होता है—जैसे डीज़ल पंप, ट्रैक्टर, और रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग।

कृषि में पारंपरिक जैविक पद्धतियाँ छोड़कर रासायनिक खेती अपनाना मृदा, जल और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह बदलाव न केवल ग्राम्य जीवन की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को भी तेज कर रहा है।

4. शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों पर दबाव

शहरी क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन गाँवों में इन सुविधाओं की कमी आज भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकारें कई योजनाएँ ला रही हैं, परंतु शहरी मॉडल को गाँवों में लाकर पर्यावरणीय असंतुलन पैदा किया जा रहा है—जैसे छोटे कस्बों में बड़े अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूभाग की अंधाधुंध कटाई।

5. जल संकट और प्रदूषण की बढ़ती समस्या

शहरों का बढ़ता जल उपभोग, ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों को प्रभावित करता है। शहरों के लिए जलाशयों का निर्माण और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, गाँवों में जल संकट को जन्म देता है। इसके अलावा, शहरों से निकलने वाले औद्योगिक और घरेलू कचरे को अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंका जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी, जल और हवा प्रदूषित हो जाती है।

गंगा जैसी पवित्र नदियाँ भी अब औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट से दूषित हो चुकी हैं। इसका असर प्रत्यक्ष रूप से गाँवों पर होता है, जो इन नदियों पर सिंचाई और पीने के पानी के लिए निर्भर हैं।

6. वातावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन

शहरों में वाहनों की अधिकता, कारखानों से निकलने वाला धुंआ, ए.सी. और ऊर्जा की अत्यधिक खपत ने ग्लोबल वॉर्मिंग को तेज किया है। इसका सीधा असर गाँवों के मौसम चक्र पर भी पड़ता है–जैसे समय पर वर्षा ना होना, अत्यधिक गर्मी, और अचानक तूफान। इससे कृषि बर्बाद होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है।

7. पारिवारिक संरचना और सामुदायिक संबंध

शहरीकरण ने संयुक्त परिवारों को तोड़कर एकल परिवार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। अब गाँवों में भी यह चलन बढ़ता जा रहा है, जिससे पारंपरिक सामाजिक ताना–बाना कमजोर हो रहा है। इसका प्रभाव पर्यावरणीय व्यवहार पर भी पड़ता है, क्योंकि सामूहिक रूप से होने वाले वृक्षारोपण, जल संरक्षण जैसे कार्य अब धीरे–धीरे कम हो रहे हैं।

8. तकनीकी क्रांति और डिजिटल गाँव

हाल के वर्षों में डिजिटल तकनीक ने ग्रामीण जीवन को छुआ है। अब स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया गाँवों में भी आम हो गए हैं। इससे शिक्षा और कृषि में सुधार की संभावनाएँ हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि तकनीकी विकास पर्यावरणीय संतुलन के साथ हो। उदाहरण के लिए, ई–कचरा का निष्पादन एक नई पर्यावरणीय चुनौती बनती जा रही है।

9. सामाजिक मीडिया और जनजागरूकता

सकारात्मक पहलू यह है कि सोशल मीडिया के ज़रिए गाँवों की समस्याएँ अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जा रही हैं। कई युवा अब पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर कर रहे हैं-जैसे जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त गाँव, और सामूहिक वृक्षारोपण। मध्य प्रदेश के एक गाँव में युवाओं ने मिलकर अपने गाँव को ठनो प्लास्टिक जोनठ घोषित किया और यह पहल अब कई अन्य गाँवों में फैल रही है।

निष्कर्ष : संतुलन की आवश्यकता

शहरीकरण कोई बुरी प्रक्रिया नहीं है–यह विकास का संकेत है। लेकिन जब यह अंधाधुंध होता है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण की अनदेखी करता है, तो यह संकट बन जाता है। गाँव और शहर दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकास ऐसा हो जो सतत हो– जिसमें पर्यावरण, संस्कृति और आजीविका तीनों का संतुलन बना रहे।

सरकार को चाहिए कि वह ग्राम्य विकास की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे–जैसे सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण।

यदि हम विकास के साथ–साथ प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो न केवल ग्राम्य जीवन बचेगा, बल्कि भारत का भविष्य भी हरित और समृद्ध होगा।

संदर्भ :

1. National Institute oef Urban Aefefairs (2020). Urbanization in India: A Complete Analysis
2. Sharma, A. (2021). Impact oef Urbanization on Rural Areas in India, Journal oef Rural Studies
3. Singh, R. (2022). The Changing Face oef Rural India, International Journal oef Development Studies

भारत की जनसंख्या 2023 में 1.428 बिलियन से अधिक हो गई है, और यह बढ़ती ही जा रही है। इस वृद्धि के साथ ही जल, भोजन, ऊर्जा और कच्चे माल जैसे संसाधनों की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे अधिक अपशिष्ट उत्पादन, संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण होता है।

हरित संक्रमण : ग्रामीण जीवन पर शहरी जीवन का प्रभाव

मयंक त्रिपाठी
तकनीकी सहायक (सिविल)

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, भले ही भौगोलिक रूप से अलग हों, परंतु सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से परस्पर गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे-जैसे शहरों का विकास होता गया, उनका प्रभाव गांवों की जीवनशैली, संसाधनों और पारिस्थितिकीय तंत्र पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा। यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी-परंतु आज की सबसे बड़ी चुनौती है: इस परिवर्तन को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना।

परंपरा और प्रकृति के संरक्षक : गांवों की मूल पहचान

ग्रामीण जीवन प्रकृति के करीब रहा है। खेत, खलिहान, तालाब, जंगल और पशुपालन की पारंपरिक पद्धतियाँ गांवों को पर्यावरण संतुलन के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करती थीं। यहां संसाधनों का दोहन सीमित था और पुन: उपयोग की संस्कृति गहराई से जुड़ी हुई थी। परंतु, जैसे ही शहरीकरण की हवा गांवों तक पहुँची, वहां का स्वरूप तेजी से बदलने लगा।

शहरी प्रभाव की हरी-भरी छाया और बढ़ते संकट

शहरों से गांवों में पहुँची आधुनिक सुविधाएं-जैसे सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं-ने जीवन स्तर को तो ऊपर उठाया, परन्तु इसके साथ-साथ बढ़ती उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति, रासायनिक खेती, जल स्रोतों का दोहन और प्लास्टिक उपयोग भी बढ़ा। यह परिवर्तन पर्यावरणीय दृष्टि से चिंताजनक है। गांवों में अब पहले जैसे तालाबों का जलस्तर नहीं दिखता, और न ही मिट्टी की उर्वरता वही रही।

पलायन और पर्यावरणीय दबाव

ग्रामीण आबादी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। इसका असर पर्यावरण पर दोहरा है-एक ओर गांवों में खेती-बाड़ी जैसे सतत कार्य कमजोर हो रहे हैं, दूसरी ओर शहरों में वाहनों की भीड़, कचरे का प्रबंधन और जलवायु पर संकट गहरा रहा है। खासकर ईंधन की खपत और बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

हरित अवसर : तकनीक और जागरूकता का उपयोग

हालांकि इस बदलाव में हरित संभावनाएं भी हैं। जैसे-जैसे गांवों में शिक्षा और तकनीक पहुंच रही है, वहां पर्यावरणीय जागरूकता भी फैल रही है। जैविक खेती, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और स्थानीय संसाधनों का टिकाऊ उपयोग बढ़ाया जा सकता है। शहरों से आए नवयुवकों द्वारा अपने गांवों में पर्यावरण हितैषी पहल शुरू की गई हैं, जो एक उम्मीद की किरण हैं।

शहरी-कृषि संपर्क और हरित अर्थव्यवस्था

शहरों की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण किसानों द्वारा होती है। यदि यह संबंध जैविक और टिकाऊ कृषि के माध्यम से हो, तो न केवल ग्रामीण आय बढ़ेगी, बल्कि भूमि और जल संसाधनों की रक्षा भी होगी। शहरी बाजारों को चाहिए कि वे पर्यावरणीय जिम्मेदारी को समझते हुए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें और किसानों को उचित मूल्य दिलाएं।

ग्रामीण पर्यटन : हरित विकास की दिशा में एक कदम

ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से शहरों के लोग गांवों की संस्कृति, जीवनशैली और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बल्कि स्थानीय पर्यावरण की रक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। यदि राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय इसे सुनियोजित रूप में बढ़ावा दें, तो यह एक सतत विकास मॉडल बन सकता है।

ऊर्जा और संसाधनों की हरित दिशा में उपयोग

अब गांवों में भी इन्वर्टर, आरओ, किचन उपकरणों और वाहनों का प्रयोग बढ़ा है। आवश्यकता है कि इन सभी के उपयोग में

ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय स्रोतों पर जोर दिया जाए। जैसे– सौर पैनल, बायोगैस संयंत्र और एलईडी लाइट्स। यह न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता को भी मजबूती देगा।

शिक्षा और संस्कृति में सामंजस्य

शहरों से प्रभावित होकर गांवों में शिक्षा का माध्यम बदल रहा है, स्कूलों के नाम शहरों जैसे हो रहे हैं, लेकिन आवश्यक है कि शिक्षा के साथ–साथ पर्यावरणीय चेतना, स्थानीय भाषा, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी बचाया जाए। यह समग्र शिक्षा ही ग्रामीणों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बना सकती है।

शहरी जीवनशैली का अनुकरण और उसके प्रभाव

गांवों में अब भीषण रूप से शहरी शैली अपनाई जा रही है– फ्लैट जैसे घर, आधुनिक फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, फ्रीज आदि। हालांकि जीवन स्तर में सुधार स्वागतयोग्य है, लेकिन अंधानुकरण से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। आवश्यकता है कि सुविधा और स्थायित्व के बीच संतुलन बनाया जाए।

नकारात्मक सामाजिक–पर्यावरणीय प्रभाव

शहरी प्रभाव के साथ कुछ सामाजिक विकृतियां भी गांवों में देखी जा रही हैं–जैसे प्रदूषण, असामाजिक गतिविधियाँ, प्लास्टिक कचरा, जल स्रोतों का अतिक्रमण आदि। गांवों का शांत, सहयोगी और सामूहिक जीवन अब प्रतिस्पर्धा और भौतिकतावाद से प्रभावित हो रहा है। यह प्रवृत्ति पर्यावरणीय संतुलन के लिए खतरे की घंटी है।

नीतियों में हरित संतुलन की आवश्यकता

सरकार की योजनाओं में अब 'शहरी सुविधाएं गांवों तक' पहुँचाने पर जोर है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन इन योजनाओं में पर्यावरणीय दृष्टिकोण भी जुड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए– हर ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों का संरक्षण, स्थानीय वृक्षारोपण योजनाएं और सौर ऊर्जा परियोजनाएं अनिवार्य रूप से लागू की जाएं।

ग्रामीण–शहरी संतुलन : भविष्य की राह

भारत में आज भी लगभग 65% जनसंख्या गांवों में रहती है। यदि यह जनसंख्या पारंपरिक ज्ञान के साथ–साथ पर्यावरण के अनुकूल आधुनिकता को अपनाए, तो भारत न केवल आर्थिक, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी वैश्विक नेतृत्व में अग्रणी बन सकता है। यह तभी संभव होगा जब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच हरित और टिकाऊ संपर्क को प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष : हरित भारत की राह पर ग्रामीण–शहरी सहभागिता

ग्रामीण जीवन पर शहरी प्रभाव अवश्य पड़ा है, परंतु अब आवश्यकता है कि इस प्रभाव को हरित दिशा में मोड़ा जाए। गांवों की प्राकृतिक धरोहर और शहरों की तकनीकी प्रगति का संतुलन ही भारत के टिकाऊ विकास का आधार बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर यदि गांव और शहर मिलकर चलें, तो न केवल अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि धरती भी हरी–भरी और स्वस्थ रहेगी।

अगले बुआई सीजन के करीब आते ही किसान फसल अवशेष जला देते हैं। फसल अवशेष जलाना गैरकानूनी है, इससे वायु प्रदूषण और भी गंभीर हो जाता है। दिल्ली का एक्यूआई 494 पर, जो अधिकतम 500 के करीब है और 'गंभीर' श्रेणी में आता है। विकल्पों की उच्च लागत के कारण जुर्माने से किसान नहीं रुकते हैं।

(https://www.reuters.com/world/india/indian-farmers-short-time-burn-crop-waste-despite-toxic-smog-2024-11-19/?utm_source)

दुख-दर्द तो आने जाने हैं कह गए बड़े लोग

कविता कुंज

डॉ.बी. बालाजी
प्रबंधक (हिं.अ. एवं नि.सं)

दुख–दर्द तो आने जाने हैं कह गए बड़े लोग
क्यों रोना ?
किसके लिए रोना ?
दर्शन साहित्य में लिखा है
महात्माओं ने कहा है
जीव मृत्यु से परे है
मृत्यु केवल शरीर को है, आत्मा अमर है
उन्हें कौन बताए दर्द भी तो शरीर को है
आत्मा किसने देखी है ?

ना परलोक, ना स्वर्ग, ना नरक देखा किसी ने
मैं तो भू लोक में जन्मा हूँ और मरूँगा भी यहीं
जाना कहीं हो तो मुझे मालूम नहीं।

आँगन में नारियल का पेड़ हरा-भरा
चंद रुपयों के लिए
ठंडी हवा-ठंडी छाँव कर दिए गायब।

पड़ोस में भी एक पेड़ कटा और एक जीव समाप्त हुआ
अब चिड़िया-तोते-कौए-कोयल-कबूतर
मेरे घर की चारदीवारी पर आकार बैठते हैं।
पेड़ की आत्मा को देखने की लाख कोशिश की मैंने ने।

उसके हाथ, उसके पाँव, उसका गला
कटते देखा मैंने खिड़की से
उसके रिश्ते–नाती रो रहे थे बेचारे
शायद सोच रहे हों, इसके बाद अपना भी नंबर आने वाला है।

घर से कितनी यादें, कितनी खुशियाँ
कितने सपने जुड़े होते हैं!!!

पेड़ों के कटने के बाद
उस जगह एक घर बनता हुआ दिखा
जो पक्षी पेड़ पर अपना आशियाना बना बैठे थे
सपने पिरोए रखे थे

हंसी–खुशी अपने परिवार के साथ रहते थे
उनकी यादें, सपने, खुशियां दफन हो गयीं
मेरे पड़ोसी के घर के नीचे।

पड़ोसी भी जानदार हैं
घर के पूजन पर बुलाने आए।
उन्होंने मेरी टूटी टांग देखी, बड़ी चिंता जताई।
अपने टांग कटे परिचितों के किस्से सुनाए
अंत में कहा बहुत दर्द होता होगा ?

क्या दर्द का एहसास हैं इन्हें ?

पेड़ों की जगह छोड़कर घर बनाते
सौंदर्य बढ़ जाता घर का
छाँव–हवा ठंडी मिलती
पर 2x4 गज जमीन छोड़ना मतलब
हजारों का नुकसान।

मैं कहने ही वाला था, मरने के बाद यही 2 गज जमीन चाहिए
मेरी पत्नी ने इशारा किया, पड़ोसी से मत लो पंगा
पड़ोसियों से दोस्ती बनाई रखनी चाहिए

पर, तब क्या करें
पड़ोसी पीठ पीछे छुरा जब घोंप दे।

हमने कंपाउंड वॉल पेड़ से दूर बनवाया
पेड़ों के लिए जगह छोड़ी थी पेड़ तो पेड़ होते हैं,
उनकी डालियाँ स्वच्छंद रूप से विकसित होती हैं।
कोई उच्छृंखल समझे तो पेड़ बेचारा क्या करे ?

एक दिन वे आए
मेरे आँगन का पेड़ कटवाने आरा लेकर
उनको कंपाउंड वॉल जो बनवानी थी।
अब इनकी आत्मा का पता नहीं
आत्मा मरी हुई है या शरीर।

तुलसी गांव

कविता कुंज

प्रतीक शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक, विपणन

वह दौर था, वह जमाना भी था
जब मिट्टी में हम खेलते थे
जब हाथ धोए बिना मिठाई खा जाते थे
जब धूल से लथपथ कपड़े भी गजब ढाते थे
जब बिना मिनरल वाटर के ही प्यास बुझाते थे
जहां रोजी–रोटी–कपड़ा–मकान सब एक ही था
न शहर की लालसा, न विदेश का पलायन
हां!!! सब एक ही था, जो हमारा तुलसी गांव था।

वही एक तुलसी गांव था जो था स्वर्ग से भी सुंदर
जहां की मां–बहने थीं देवी के समान
हर आंगन में होता था तुलसी का पूजन
हर पुरुष की सुंदर संगिनी, न थी किसी अप्सरा से कम
युग युगांतरों तक
सुंदर रहा ऐसा मेरा तुलसी गांव
पर वह भी एक दिन आया
जब फीकी पड़ गई पुरखों की नसीहत
जब आई शहरी तालीम
और लाई पर्यावरण की तर्ज पर ऊंचे–ऊंचे मकान,
नदी पर बांध और कोयले की खदान।

अपनी मायूसी अपनी नेकी
देख–देख कर रोता रहा तुलसी गांव।

वे लोग जो करते थे पुरखों की नसीहत पर गुरुर
आज वही लोग लगाते हैं उन्हीं की वसीयत पर मोहर।

पर, मैं आज भी वही हूं, मेरे बेटों में
आज भी वही हूं–तुम्हारा तुलसी गांव।

तुमने दिया शहर का झूठा नाम जिसे
मैं वही हूं, हां!!! मैं वही हूं– तुलसी गांव।

जिसकी नदी को तुमने कर दिया नाले में तबदील
हां, मैं वही हूं तुलसी गांव
जिसने देखा अपने उजड़े आम बाग़ान में नया हेलीपैड
क्यों गए तुम छोड़ मुझको बताओ
क्यों फेर लिया मुंह मुझसे बताओ
जब था खुला आसमान, साफ हवा और शीतल जल
अब बताओ मैं क्या करूं जब लुट गया मेरा जमीर
अब ना रहा पशु–धन, ना रही फसल,
अब रो रहे हो तुम सब बिन नीर।

पर्यावरण ही थी मेरी नसीहत, पर्यावरण ही थी मेरी जागीर
पर्यावरण ही था मेरा रुआब और पर्यावरण ही था मेरा वजूद।

जो मेरा था वह सब तेरा था, जो मेरा था वह सब तेरा था।
आज मैं नहीं इसलिए तू नहीं, आज मैं नहीं इसलिए तू नहीं।

फिर कहता हूं मेरे बच्चे
हर घर हर शहर को बना ऐसा, जैसा था तुम्हारा तुलसी गांव
इससे पहले कि
हर गांव हर शहर में आ जाए अश्कों का सैलाब
बना लो अपने घर-शहर का पर्यावरण
जैसा था तुम्हारा तुलसी गांव।

तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तुलसी वायुमंडल को शुद्ध करती है और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाती है। कीटाणुओं और मच्छरों को दूर रखने की प्राकृतिक क्षमता रखती है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन में शिक्षा की भूमिका

आलेख

सी. सुरेश रेड्डी
जे ओ एस (ए एम टी एल)

लोगों ने भ्रष्टाचार को अपने गंदे पैरों के साथ अपने दिमाग में घुसने दिया है, नैतिकता और आचरण को गिराया है, मानवीय मूल्यों और समाज को नष्ट किया है। यह अब एक महामारी की तरह फैल रहा है जो सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहा है और धीरे–धीरे एक राक्षस में तब्दील हो रहा है, जो हमारे देश को नष्ट करने की धमकी दे रहा है।

भ्रष्टाचार क्या है ?

भ्रष्टाचार को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बेईमानी और धोखाधड़ी के आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विशेष रूप से धन से संबंधित मामलों में, इसकी परिभाषा पहले की तुलना में अब अधिक व्यापक हो गई है। इसमें कार्यालय/कार्य के बहुमूल्य समय की बर्बादी और दुरुपयोग शामिल है, जिससे उस दक्षता और उत्पादन में कमी आती है जिसके लिए व्यक्ति को भुगतान किया जाता है।

विस्तार से कहें तो यह अवैध तरीकों से संसाधन या सेवाएं प्राप्त करने के लिए शक्ति या धन का दुरुपयोग है। यह समाज में सबसे अधिक बहस का विषय है क्योंकि इसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। भ्रष्टाचार के कारण संसाधनों का धनी और शक्तिशाली लोगों के हाथों में संकेन्द्रण हो जाता है, जिससे गरीब लोग निराश और असहाय हो जाते हैं।

औद्योगीकरण और शहरीकरण के आगमन से बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिससे कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का संकेन्द्रण हो गया है, जिससे आम जनता का शोषण हुआ है।

छोटे–मोटे रिश्वतखोरी से लेकर बड़े–बड़े घोटालों तक भ्रष्टाचार की व्यापक श्रृंखला ने हमारे संसाधनों को नष्ट कर दिया है और भारत को आज सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक बना दिया है।

गरीब वे लोग हैं जिनका अक्सर भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों द्वारा निर्दयतापूर्वक शोषण किया जाता है। इसका एक प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है। गरीबों के पास शिक्षा तक बहुत कम या कभी–कभी कोई पहुंच नहीं होती, जिससे वे शोषण का आसान लक्ष्य बन जाते हैं। इसलिए, शिक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ़ प्राथमिक हथियारों में से एक है। गरीबों को शिक्षित करने से उन्हें अपने अधिकारों का एहसास होगा और उन्हें अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिलेगा। यह उन्हें स्वतंत्र बनाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ युद्ध में उन्हें एकजुट भी करेगा।

केरल संभवत: भारत का सबसे कम भ्रष्ट राज्य है, जिसका श्रेय इसकी उच्च साक्षरता दर यानी 97% को जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए जो सभी को प्रदान की जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अभाव है और यह लोगों में मानवीय मूल्यों का संचार करके भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहायक हो सकती है।

आध्यात्मिक शिक्षा का उपयोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। इससे कम से कम भ्रष्ट लोगों में ईश्वर के प्रति भय पैदा होगा और उन्हें समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का अहसास भी होगा। शिक्षा की शक्ति एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इसकी अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार हमारे देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

इस अद्भुत भूमि के नागरिक होने के नाते, हमारा यह कर्तव्य है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएँ और अपने देश को स्वच्छ बनाएँ। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर दिमागों का देश बनाना है, तो इस प्रयास में समाज के तीन सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे हैं माताएँ, पिता और शिक्षक। इन तीनों में से हमारे देश से भ्रष्टाचार को मिटाने में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ हम अपने पड़ोसी देश "चीनह्न का जीवंत उदाहरण ले सकते हैं, जिसने अपने शिक्षकों के मूल्यों और प्रतिष्ठा को उन्नत किया और बदले में शिक्षकों ने चीनी छात्रों के भाग्य को बदल दिया और उन्हें विकसित यूरोपीय और पश्चिमी देशों से आगे कर दिया।

इसलिए, शिक्षा की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह भ्रष्टाचार के राक्षस को मारने वाली तलवार बन सकती है तथा हमारे देश और समाज को उसके अत्याचार से मुक्त कर सकती है।

भ्रष्टाचार की समस्या का आध्यात्मिक समाधान

भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो भ्रष्ट न हों और निस्संदेह, ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिकता ही पैदा करती है। एक कहावत है कि हिंसा मन से शुरू होती है। यह भ्रष्टाचार के लिए भी सच है: भ्रष्टाचार मन से शुरू होता है। अगर हम अपनी सोच बदल सकें, तो हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि हमने कम से कम 50% भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। जो चीज दिल और दिमाग को बेहतर बनाती है, वह है आध्यात्मिकता। जब एक हवाई जहाज उड़ान भरता है, तो वह सब कुछ पीछे छोड़ देता है और एक उच्च स्थान पर पहुंच जाता है, जहां वह बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य की ओर उड़ने में सक्षम होता है। इसी तरह, एक आध्यात्मिक साधक एक उच्च स्थान पर उड़ने में सक्षम होता है जहां वह नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होता है।

आध्यात्मिकता के दो पहलू हैं: सिद्धांत और व्यवहार। मूल रूप से आध्यात्मिकता जीवन के मुद्दों के प्रति एक गैर–भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जो भौतिकवादी हितों पर आधारित दूसरे दृष्टिकोण के विपरीत है। भ्रष्टाचार का मूल कारण भौतिकवादी दृष्टिकोण है।

व्यावहारिक आध्यात्मिकता व्यक्ति को दैनिक जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को समाहित करने में सक्षम बनाती है और जो लोग ऐसा करते हैं, वे सभी प्रकार के भ्रष्ट आचरण से खुद को दूर रखने में सक्षम होते हैं। व्यावहारिक आध्यात्मिकता का एक पहलू कर्तव्य–चेतना है जो यह प्रेरित करती है। अधिकारों के प्रति जागरूक व्यक्ति केवल वही देख सकता है जो उसके अपने हित में है, जबकि कर्तव्य के प्रति जागरूक व्यक्ति दूसरों की भलाई को देखता है और ऐसा करते हुए, कभी भी भ्रष्ट आचरण की ओर नहीं गिर सकता।

लोगों में आध्यात्मिकता कैसे पैदा की जाए? मूल रूप से, यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा का एक हिस्सा है। शिक्षा का मतलब है मन का प्रशिक्षण, जिसमें उच्च मूल्यों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को फैलाने के लिए, हमें खासकर स्कूली शिक्षा के दौरान मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, जो जीवन की तैयारी का समय है और अगर हम एक आध्यात्मिक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें मूल्य आधारित शिक्षा को अपनाना होगा।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को अपने कार्यों का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर करना चाहिए – जो जिम्मेदारी की भावना रखने का एक प्रमुख कारक है। जो व्यक्ति इस तरह का दृष्टिकोण विकसित करता है, वह चीजों को मूल्य के संदर्भ में देखने में सक्षम होता है। वह सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम होता है।

एक कहावत है: ''बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो चीजों के सापेक्ष मूल्य को जानता है।'' एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जिसका चरित्र पूर्वानुमानित होता है। ये सभी गुण आध्यात्मिक प्रशिक्षण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए, सुधारकों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को कर्तव्य–सचेत बनने के लिए प्रशिक्षित करें – क्योंकि कर्तव्य–सचेत व्यक्ति कभी भी भ्रष्टाचार जैसी किसी नकारात्मक गतिविधि में खुद को शामिल नहीं कर सकता।

आध्यात्मिकता भावनाओं को नियंत्रण में रखने में मदद करती है और मन को शांति प्रदान करती है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाता है, छात्रों को शाश्वत मूल्यों और सत्यों को आत्मसात करने में मदद करेगी जो उन्हें न केवल अपनी बौद्धिक क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाती है बल्कि समाज में जिम्मेदार इंसान के रूप में अपनी भूमिका निभाने में भी सक्षम बनाती है।

भौतिकवादी व्यक्ति आध्यात्मिक लक्ष्यों या मूल्यों की तुलना में भौतिकता के बारे में अधिक चिंतित रहता है। भ्रष्टाचार भौतिकवादी समाज की एक घटना है जबकि आध्यात्मिकता विकसित व्यक्तियों की घटना है। केवल ऐसे व्यक्ति ही एक गैर भ्रष्ट समाज का निर्माण कर सकते हैं। आध्यात्मिकता और भ्रष्टाचार एक साथ नहीं चल सकते।

अगर समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त होना है, तो उसे विकसित या कम से कम, विकासशील व्यक्तियों से बना होना चाहिए, जिन्हें सही और गलत के बारे में काफी मजबूत समझ हो। भ्रष्टाचार की समस्या का यही एकमात्र समाधान है। यही सही शुरुआत है और केवल सही शुरुआत ही वांछित लक्ष्य तक पहुंचना संभव बना सकती है।

प्रतिज्ञा से लेकर अभ्यास तक: संरक्षा उत्कृष्टता के लिए मिधानि का समग्र दृष्टिकोण

एम. मल्ला रेड्डी
प्रबंधक (संरक्षा)

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) ने 4 से 10 मार्च, 2025 तक 54वां राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह बड़े उत्साह और जिम्मेदारी की भावना के साथ मनाया। सभी के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे संगठन में संरक्षा और तैयारी की संस्कृति को मजबूत करना था।

सुरक्षित कार्यस्थलों की ओर एक कदम

राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह हर साल राष्ट्रीय संरक्षा परिषद के तत्वावधान में मनाया जाता है, ताकि औद्योगिक श्रमिकों में सुरक्षा चेतना को बढ़ावा दिया जा सके और कार्यस्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व पर जोर दिया जा सके। मिधानि में, संरक्षा हमेशा इसके मूल मूल्यों का एक अभिन्न अंग रही है। इस सप्ताह ने कार्यबल को फिर से सक्रिय करने और साझा जिम्मेदारी के रूप में संरक्षा के महत्व को दोहराने के लिए एक मंच प्रदान किया।

दैनिक अनुस्मारक के लिए संरक्षा पोस्टर

सप्ताह भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में, मिधानि संयंत्र में निर्धारित स्थानों पर संरक्षा पोस्टर रणनीतिक रूप से लगाए गए थे। ये पोस्टर सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों और आगंतुकों को उनके दैनिक कार्य में संरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में दैनिक दृश्य अनुस्मारक के रूप में काम करते थे। पोस्टरों में प्रमुख संरक्षा संदेश, व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग पर दिशा–निर्देश, आपातकालीन संपर्क जानकारी और विभिन्न संयंत्र क्षेत्रों के लिए बुनियादी 'क्या करें और क्या न करें' पर प्रकाश डाला गया था। उन्हें सूचनात्मक और आकर्षक दोनों तरह से डिज़ाइन किया गया था, जिससे श्रमिकों को रुकने और अपने संरक्षा अभ्यासों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

संरक्षा शपथ के माध्यम से प्रतिबद्धता की पुष्टि

सप्ताह की शुरुआत गंभीर प्रतिबद्धता की भावना के साथ करने के लिए, पूरे संयंत्र में कई स्थानों पर संरक्षा प्रतिज्ञा ली गई। सभी विभागों के कर्मचारी शपथ लेने के लिए एक साथ आए, सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने, असुरक्षित प्रथाओं की रिपोर्ट करने और न केवल अपने बल्कि अपने सहकर्मियों के जीवन की रक्षा करने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि की। यह प्रतीकात्मक कार्य संरक्षा की संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास का एक शक्तिशाली अनुस्मारक था।

आपातकालीन तैयारी : हाइड्रोजन संयंत्र में मॉक ड्रिल

संरक्षा सप्ताह का मुख्य आकर्षण हाइड्रोजन संयंत्र में आयोजित मॉक ड्रिल था, जिसका उद्देश्य मिधानि की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की तत्परता का मूल्यांकन करना था। टीम किसी संकट का कितनी तेज़ी से और प्रभावी ढंग से सामना कर सकती है, इसका आकलन करने के लिए एक खतरनाक परिदृश्य का अनुकरण किया गया। इस ड्रिल में अलार्म सिस्टम, संचार प्रोटोकॉल, बचाव अभियान, निकासी प्रक्रिया और विभिन्न आपातकालीन टीमों के बीच समन्वय जैसे विभिन्न तत्वों का परीक्षण किया गया।

इस व्यावहारिक सिमुलेशन ने न केवल ताकत और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद की, बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों को मूल्यवान व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। पर्यवेक्षकों और संरक्षा अधिकारियों ने उच्च स्तर की तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया की दक्षता पर ध्यान दिया, जिससे वास्तविक समय की आपात स्थितियों से निपटने के लिए मिधानि की क्षमता को बल मिला।

शालाओं में संरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का सशक्तिकरण

पूरे सप्ताह के दौरान, विभिन्न उत्पादन इकाइयों में शाला संरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इन सत्रों को इंटरैक्टिव और व्यावहारिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो प्रत्येक इकाई में शामिल विशिष्ट जोखिमों और मशीनरी के अनुरूप थे। समाहित किए गए विषयों में मशीन संरक्षा, सामग्री हैंडलिंग, अग्नि संरक्षा, रासायनिक हैंडलिंग, लॉकआउट–टैगआउट प्रक्रियाएं और प्राथमिक चिकित्सा शामिल थे।

प्रशिक्षकों ने संरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी के परिणामों को रेखांकित करने के लिए वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज़ और पिछली घटनाओं के बारे में बताया। कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, सवाल पूछे और अपने अनुभव साझा किए, जिससे सीखने का माहौल समृद्ध हुआ। इन सत्रों ने कर्मचारियों को जिम्मेदारी से काम करने और आपात स्थितियों के दौरान तेज़ी से प्रतिक्रिया करने के लिए ज्ञान और आत्मविश्वास से सशक्त बनाया।

प्रबंधन की भूमिका और सक्रिय भागीदारी

मिधानि के शीर्ष प्रबंधन ने संरक्षा सप्ताह की पहल को अपना पूरा समर्थन दिया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रशिक्षण सत्रों का दौरा किया, कर्मचारियों को संबोधित किया और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सुरक्षित कार्यस्थल बनाए रखने में प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और सुरक्षा बुनियादी ढांचे और प्रोटोकॉल को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयासों का आश्वासन दिया।

इस शीर्ष-स्तरीय दृष्टिकोण ने इस संदेश को पुष्ट करने में मदद की कि संरक्षा केवल अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक मौलिक संगठनात्मक मूल्य है। वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति और भागीदारी ने कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया, जिससे उन्हें अपने–अपने कार्यस्थलों में संरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया गया।

भविष्य की रूपरेखा : निरंतर सुधार की संस्कृति

54वें राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह के समापन पर, मिधानि ने संरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सप्ताह के दौरान की गई गतिविधियों ने न केवल ज्ञान को ताज़ा किया और तैयारियों में सुधार किया, बल्कि संरक्षा नवाचार, जोखिम प्रबंधन और व्यक्तिगत जवाबदेही के बारे में बातचीत को भी बढ़ावा दिया।

सप्ताह से प्राप्त सीख और फीडबैक को संकलित किया जाएगा और भविष्य की सुरक्षा पहलों और सुधारों की योजना बनाने के लिए समीक्षा की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सप्ताह के दौरान बनाई गई गति पूरे वर्ष जारी रहे, नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और आवधिक संरक्षा लेखापरीक्षा निर्धारित की गई हैं।

निष्कर्ष

मिधानि द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का आयोजन केवल एक वार्षिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि संरक्षा मूल्यों के साथ एक सार्थक जुड़ाव था जो कंपनी के डीएनए में अंतर्निहित हैं। इंटरैक्टिव सत्रों, व्यावहारिक अभ्यासों और सक्रिय नेतृत्व के माध्यम से, संगठन ने एक संरक्षित, अधिक लचीला कार्यस्थल बनाने की दिशा में अपने सक्रिय दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया।

इस सप्ताह को इतनी ईमानदारी और पूरी योजना के साथ मनाकर, मिधानि ने एक बार फिर यह प्रदर्शित किया है कि संरक्षा कोई घटना नहीं है – यह एक सतत यात्रा है। सभी हितधारकों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता संगठन के दृष्टिकोण को दर्शाती है कि न केवल सामग्री और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति – अपने लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना भी है।

करदाताओं के लिए जानना जरूरी है

गरिमा ओझा
सहायक प्रबंधक
(वि. एवं ल.)

पुरानी कर व्यवस्था बनाम नई कर व्यवस्था: वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए एक विश्लेषण

परिचय

भारत मे पहली बार बजट 2020 में नई कर व्यवस्था का प्रावधान रखा गया । हालांकि, 01 अप्रैल 2023 से भारत में नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर प्रणाली के रूप में लागू किया गया । इसका सीधा प्रभाव वेतनभोगी कर्मचारियों और अन्य करदाताओं पर पड़ता है। यदि कोई करदाता पुरानी कर व्यवस्था को अपनाना चाहता है, तो उसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा कि वह पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार कर की कटौती का विकल्प चुनना चाहता है, अन्यथा बिना किसी विकल्प के चयन पर उसके कर की गण्ना नई कर व्यवस्था के अनुसार की जायेगी ।

आज इस लेख के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि करदाताओं को कर व्यवस्था का चुनाव कैसे करना चाहिये। यह समझने के लिये हम पुरानी और नई कर व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे और यह जानेंगे कि कौन–सी व्यवस्था अधिक फायदेमंद हो सकती है।

1. आय की गणना

आयकर की गणना किसी व्यक्ति की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाती है। इसमें वेतन, बोनस, भत्ते और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय शामिल होती है। पुरानी और नई कर व्यवस्था में आय की गणना करने का तरीका समान ही रहता है, लेकिन कई छूट और कटौतियों में अंतर है।

2. छूट**

छूट वे विशेष प्रावधान होते हैं, जो करदाताओं को कर में राहत प्रदान करते हैं। पुरानी कर व्यवस्था में करदाताओं को मानक कटौती, के साथ धारा 10 के अन्तर्गत कई तरह की छूट का प्रावधान है जैसे – मकान किराया भत्ता, पोशाक भत्ता, परिवहन भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत और अन्य कई लाभ वही, नई कर व्यवस्था में अधिकांश छूटों को हटा दिया गया है, केवल मानक कटौती को छोड कर एवं परिवहन भत्ता (केवल शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी के लिए) । निम्न सारणी के माध्यम से दोनो कर व्यवस्था मे छूट के संदर्भ मे अंतर को दर्शाने का प्रयास किया गया है : –

मदें	पुरानी कर व्यवस्था	नई कर व्यवस्था
धारा 10 के तहत भत्ते में छूट		
धारा 10(13ए) के तहत मकान किराया भत्ता	✓	×
धारा 10(5) के तहत अवकाश यात्रा रियायत	✓	×
धारा 10(14) के तहत बच्चों की शिक्षा भत्ता	✓	×
धारा 10(14) के तहत बच्चों का छात्रावास भत्ता	✓	×
धारा 10(14) के तहत पोशाक भत्ता	✓	×
धारा 10(14) के तहत परिवहन भत्ता	✓*	✓*
धारा 10(14) के तहत सहायक भत्ता	✓	×
धारा 16 के तहत भत्ते में छूट		
मानक कटौती	50000	75000
रोजगार पर कर	2400	×
* केवल शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी के लिए		
धारा 24(बी) के तहत आवास ऋण के ब्याज पर कटौती		
स्व–अधिकृत मकान संपत्ति	✓	×
किराया मकान संपत्ति#	✓	✓

पुरानी कर व्यवस्था में मकान संपत्ति मद में होनी वाली हानि को अन्य मद की आय से वर्तमान वर्ष में समायोजित किया जा सकता है , परन्तु नई कर व्यवस्था में केवल यह हानि मकान संपत्ति आय से ही समायोजित किया जा सकता है और शेष बची हानि को आगामी वर्षो में गृह संपत्ति आय से ही समायोजित किया जा सकता है। (पुरानी एवं नई दोनों कर व्यवस्था में)

पुरानी कर व्यवस्था के समान ही नई कर व्यवस्था में भी सेवानिवृति पर प्राप्त ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण पर क्रमशः 20 लाख एवं 25 लाख तक कर नहीं लगता।

और साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या भविष्य निधि (पीएफ) में नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान कर मुक्त रहता है।

3. कटौतियाँ**

कटौतियाँ कर की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये कर योग्य आय को कम करने में मदद करती हैं। जहाँ पुरानी कर व्यवस्था मे कई प्रकार की कटौतियों के प्रवधान है जैसे धारा 80सी के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती (PPF, EPF, LIC, NSC आदि), धारा 80डी के तहत चिकित्सा बीमा पर कटौती, धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत NPS मे स्व अंशदान की कटौती, 80टीटीए मे बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की कटौती, 80जी के तहत विभिन्न प्रकार के दान की कटौती आदि।

वहीं नई कर व्यवस्था में सभी प्रकार की कटौतियों को निकाल दिया है, केवल निम्न कटौतियों के-

- धारा 80सीसीडी (1) के तहत मिलने वाली कटौती (नियोक्ता द्वारा NPS मे किया जाने वाला अशदान)
- 80सीसीह्च अग्नि पथ योजना में अंशदान

** **सभी प्रकार की कटौतियों एवं छूट की अधिकतम राशि की गणना निम्न प्रकार की जायेगी-**

- **असल व्यय की गई राशि या**
- **संबंधित धारा में उल्लिखित राशि/मौद्रिक सीमा दोनों में से जो भी कम हो।**

4. कर की दरें एवं धारा 87A की छूट^

नई कर व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, इसकी सरल कर दरें हैं, जो इस प्रकार है -

कर योग्य आय की राशि	पुरानी कर व्यवस्था	नई कर व्यवस्था
0–250000	0%	
250001–500000	5%	
500001–1000000	20%	-
>1000000	30%	
0–400000	–	0%
400001–800000		5%
800001–1200000		10%
1200001–1600000		15%
1600001–2000000		20%
2000001–2400000		25%
>2400000		30%
धारा 87 ए की छूट	5,00,000.00	12,00,000.00
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उप कर	4%	4%

^निर्धारण वर्ष 2026–27 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये

धारा 87A के तहत वह करयोग्य राशि वर्णित कि गई है जिस सीमा तक यदि करदाता की करयोग्य आय होने पर सम्पूर्ण कर की छूट धारा 87A के अंतर्गत मिल जायेगी। पुरानी कर व्यवस्था व नई कर व्यवस्था में यह राशि क्रमशः ₹ 5 लाख और ₹ 12 लाख है।

5. उदाहरण: आइए, एक उदाहरण के माध्यम से दोनों कर व्यवस्थाओं को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं -

मदें	श्रीमान ए पुरानी कर व्यवस्था	श्रीमान ए नई कर व्यवस्था	श्रीमान सी पुरानी कर व्यवस्था	श्रीमान सी नई कर व्यवस्था
वेतन मद के अंतर्गत आय	13,00,000	13,00,000	13,00,000	13,00,000
धारा 10 के तहत भत्ते में छूट				
धारा 10(13ए) के तहत मकान किराया भत्ता	40,000	0	0	0
धारा 10(5) के तहत अवकाश यात्रा रियायत	25,000	0	50,000	0
धारा 16 के तहत भत्ते में छूट				
मानक कटौती	50,000	75,000	50,000	75,000
रोजगार पर कर	2,400	0	2,400	0
अध्याय VI–ए के तहत कटौती				
80सी के तहत छूट	1,50,000	0	1,50,000	0
धारा 80 सीसीडी (1) के तहत कटौती		25,000		0
धारा 80 डी के तहत कटौती	50,000	0	50,000	0
धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत कटौती	50,000	0	50,000	0
वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य आय	9,32,600	12,00,000	9,47,600	12,25,000
कर की राशि	1,02,981	62,400	1,06,101	66,300
वेतन आय के आधार पर कर व्यवस्था का चयन	×	87 ए की छूट	×	✓

उक्त उदाहरण में दो ऐसे व्यक्तिओं को दर्शाया गया है जिनकी आय समान है परंतु व्यय एवं निवेश की आदत भिन्न-भिन्न है । यदि हमे केवल वेतन आय के आधार पर निर्णय लेना हो तो उक्त सारणी के आधार पर होगा। जिसमें कि दोनों को ही नई कर व्यवस्था में लाभ है क्योंकि श्रीमान ए को धारा 87 ए की छूट है वही श्रीमान सी को कर का दायित्व कम है ।

यदि मकान संपत्ति की आय का समायोजन करने के बाद विचार करे तो परिस्थिति थोडी अलग है। चूकि, श्रीमान ए को 87 ए की छूट मिल रही है तो उनका निर्णय वही रहेगा परंतु यदि श्रीमान ए को धारा 80 सीसीडी (1) के तहत NPS की कटौती न होती तो वह भी पुरानी कर व्यवस्था चुनता। वही, श्रीमान सी का निर्णय बिलकुल विपरित हो गया है ।

मदें	श्रीमान ए पुरानी कर व्यवस्था किराया मकानसंपत्ति	श्रीमान ए नई कर व्यवस्था किराया मकानसंपत्ति	श्रीमान सी पुरानी कर व्यवस्था स्व–अधिकृत	श्रीमान सी नई कर व्यवस्था स्व–अधिकृत
मकान संपत्ति	72,000	72,000	0	0
गृह संपत्ति से आय (या स्वीकार्य हानि)।	−21,600	−21,600	0	0
मकान किराया	−3,00,000	−3,00,000	−3,00,000	−3,00,000
धारा 24(ए) के तहत मानक कटौती 30%	−2,49,600	−2,49,600	−2,00,000	0
धारा 24(बी) के तहत गृह ऋण पर ब्याज पर कटौती	−2,00,000	0	−2,00,000	0
गृह संपत्ति से आय (या स्वीकार्य हानि)।	−49,600	−2,49,600	0	0
वेतन मद आय से समायोजित हो सकने वाली हानि	7,32,600	12,00,000	7,47,600	12,25,000
आगामी वर्षो मे गृह संपत्ति आय से समायोजित हो सकने वाली हानि				
वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य आय	7,32,600	12,00,000	7,47,600	12,25,000
कुल आय				
कर की राशि	61,381	62,400	64,501	66,300
कर व्यवस्था का चयन	✓	87 ए की छूट	✓	×

6. महत्वपूर्ण बिंदु

1. 01 अप्रैल 2023 से नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बन गई है ।
2. यदि आप पुरानी कर व्यवस्था को चुनना चाहते हैं तो आपको वर्ष की शुरुआत में अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा ।
3. यदि कर दाता के पास कोई व्यावसायिक आय नहीं है तो व्यवस्था का चयन हर साल किया जा सकता है ।
4. कर व्यवस्था का चयन व्यक्ति दर व्यक्ति अलग–अलग होगा ।
5. किसी भी कर व्यवस्था का चयन करने से पहले तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए ।

निष्कर्ष

नई कर व्यवस्था सरल है और इसमें कर की दरें कम रखी गई हैं, लेकिन इसमें कोई अतिरिक्त कटौती और छूट उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर, पुरानी कर व्यवस्था में विभिन्न छूट और कटौतियों का लाभ मिलता है, जिससे करदाता को अधिक बचत करने में मदद मिल सकती है।

इसलिए, करदाताओं को अपने खर्च, निवेश वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर दोनों कर व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद निर्णय लेना चाहिए कि कौन–सी कर व्यवस्था उनके लिए उपयुक्त है।

कहानी

रोहित निगुडकर
उ.म.प्र. (वित्त)

....आज बह रहा है ज़माने में !

दोस्तों आज एक पुराना किस्सा आपके साथ साझा करता हूँ। मुझे और मेरे एक मित्र को एक बाँध की साइट पर ऑडिट के लिए जाना था।

वो एक छोटा सा गांव था। शौचालय वगैरह थे पर पानी आता जाता रहता था।

एक सुबह हम दोनों दरवाजे पर हुई दस्तक से उठ गए।

देखा तो केयर टेकर था। उसने बताया कि आज पानी नही आएगा।

हम दोनो की हालत खराब थी। नहाना तो छोड़ सकते हैं पर प्रकृति का आदेश तो मानना ही पड़ता हैं उसे तो टाल नही सकते।

आखिर हम दोनो ने सुबह का काम अत्यल्प जल से निपटाया लेकिन किये हुए पर पानी न फिरा पाए।

जब भी बाथरूम जाते हमारे पाप मुँह चिड़ाते हुए हमें घूर रहे होते।

जब अति हो गई तो मेरा दोस्त करीब के होटल से एक बाल्टी पानी खरीद के लाया और शौचालय में उडेल दिया।

कुछ दिन बाद दफ्तर से आकर हम लोग चहल कदमी करते घूम रहे थे तो देखा की एक जगह पाइप लाइन फूट गई है और पानी सड़कों पर बह रहा है।

तपाक से मेरा दोस्त शरारती अंदाज में बोला।

– देख रहे हो रोहित भाई ?

मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। उसने अमिताभ की आवाज़ की नकल करते हुए कहा

–कल तक मयस्सर नही था पैखानें में,
आज बहता फिर रहा है ज़माने में।

और हम दोनो हो हो कर के हँस पड़े।

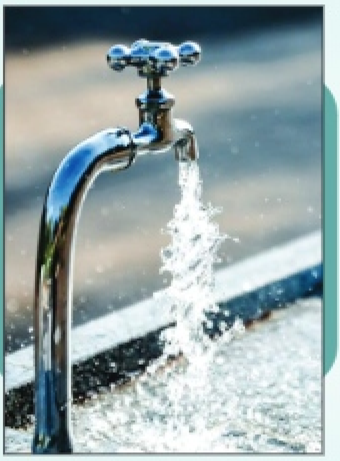

भारत में पानी की बर्बादी एक बड़ी चिंता का विषय है, खास तौर पर देश के सीमित जल संसाधनों और बढ़ती मांग को देखते हुए। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन उसके पास जल संसाधनों का सिर्फ़ 4% है, जिससे यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जल-तनावग्रस्त देशों में से एक बन गया है। भारत में पानी की बर्बादी एक बड़ी चिंता का विषय है, खास तौर पर देश के सीमित जल संसाधनों और बढ़ती मांग को देखते हुए।

अनुमान बताते हैं कि भारत लापरवाही और अकुशल उपयोग सहित विभिन्न कारकों के कारण प्रतिदिन लगभग 49 बिलियन लीटर पानी बर्बाद करता है।

(https://neerain.com/49-billion-liters-of-water-is-wasted-daily-in-the-country-due-to-carelessness/?utm_source)

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दि. 16.10.2024 को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में एवीएनएल और मिधानि के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग को चिह्नित करते हुए श्री सत्यव्रत मुखर्जी, निदेशक (संचालन), एवीएनएल और श्री टी. मुत्तुकुमार, निदेशक (उत्पादन एवं विपणन), मिधानि द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता बख्तरबंद वाहनों के डिजाइन, विकास और विपणन पर केंद्रित है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर, श्री संजय द्विवेदी, सीएमडी, एवीएनएल और श्री संजीव कुमार भोला, सीजीएम, वीएफजे और मिधानि के अधिकारीगण मौजूद थे। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से दोनों संगठन अब सभी एवीएनएल इकाइयों में बख्तरबंद प्लेटों की मांग को पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाएँगे।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2024

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार 28.10.2024 से 03.11.2024 तक 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' विषय पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह संपन्न हुआ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024 का आरंभ डॉ. एस.के. झा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि द्वारा 28.10.2024 को 1430 बजे सत्यनिष्ठा शपथ दिलाने के साथ शुरू हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में सीए एन. गौरी शंकर राव, निदेशक (वित्त), श्री टी. मुत्तुकुमार, निदेशक (उत्पादन एवं विपणन) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा मिधानि के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह –2024 के उद्घाटन सत्र के दौरान, मिधानि के निदेशकों द्वारा 'प्रोक्यूर्मेंट ऑफ वर्क्स इन मिधानि' का मैनुअल जारी किया गया है।

सप्ताह के दौरान इस वर्ष के विषय 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' पर कर्मचारियों के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया।

‘भ्रष्टाचार विरोधी अभियान’, ‘मिधानि खरीद मैनुअल 2023 फॉर गुड्स एंड सब–कॉन्ट्रैक्टिंग’ और ‘स्थायी आदेश’ जैसे विषयों पर विभिन्न प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की गईं। सीवीसी के निर्देशानुसार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए समाज के हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रेता बैठक (ऑनलाइन), ग्राहक शिकायत निवारण सत्र (ऑनलाइन) और मिधानि हैदराबाद संयंत्र के आसपास के क्षेत्र में 4 किलोमीटर का वॉकथॉन आयोजित किया गया। मिधानि के सतर्कता विभाग के अनुरोध पर, मिधानि टाउनशिप के बीपीडीएवी स्कूल के प्रबंधन द्वारा सप्ताह के दौरान आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में छात्रों के लिए पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन और नारा लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

सप्ताहभर के समारोह का समापन 04.11.2024 को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डॉ. एस.के. झा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन. गौरी शंकर राव, निदेशक (वित्त), श्री टी. मुत्तुकुमार, निदेशक (उत्पादन एवं विपणन) तथा मिधानि के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सतर्कता गृह पत्रिका ‘जागृति’ का विमोचन किया गया। सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रतिबद्ध मिधानि के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्र गान से हुआ।

मिधानि में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक ‘सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि’ विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एस.के. झा द्वारा सत्यनिष्ठा शपथ के साथ हुआ। सप्ताह के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों, मिधानि खरीद मैनुअल, और स्थायी आदेशों से जुड़े ऑनलाइन क्विज़, विक्रेता बैठकें, ग्राहक संवाद सत्र और वॉकथॉन जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। बीपीडीएवी स्कूल में छात्रों के लिए पोस्टर, निबंध और नारा लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। समापन समारोह में ’जागृति’ पत्रिका का विमोचन और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिधानि की प्रतिबद्धता के संकल्प के साथ हुआ।

76वां गणतंत्र दिवस समारोह

मिधानि ने 76वां गणतंत्र दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया, जिसकी शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से हुई। निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी प्रभारी सीए एन. गौरी शंकर राव ने देश के प्रति मिधानि की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कंपनी की प्रमुख उपलब्धियाँ साझा कीं। उन्होंने सीएसआर के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में कंपनी के योगदान का उल्लेख भी किया। समारोह में बीपीडीएवी स्कूल के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ जिसमें मिधानि के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे।

एयरो इंडिया 2025 में सहभागिता

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) ने 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2025 में सफलतापूर्वक भाग लिया। इस मंच पर मिधानि ने तीन स्वदेशी रूप से विकसित एयरोस्पेस सामग्रियों का अनावरण किया–निकल मिश्र धातु बिलेट्स, मिश्र धातु ए152 फर्जड बार्स और सुपरनी 41 प्लेट्स जो भारत की रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मिधानि के विशिष्ट उत्पाद तेजस फाइटर जेट और इसरो मिशनों में उपयोगी हैं। कार्यक्रम 'सामर्थ्य' में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मिधानि के कर्मचारियों को रणनीतिक मिश्र धातुओं के स्वदेशीकरण में योगदान हेतु सम्मानित किया। मिधानि ने इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के साथ एमओयू भी किए, जिससे इसकी आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक उपस्थिति मजबूत हुई। 'मेक इन इंडिया' के तहत मिधानि स्वदेशी निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

टीबी के प्रारंभिक पहचान उपकरण और पोषण किट प्रायोजित

मिधानि ने टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के '100 दिवसीय गहन अभियान' के अंतर्गत 15 फरवरी 2025 को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हैदराबाद में तपेदिक (टीबी) उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तेलंगाना टीबी अधिकारियों के अनुरोध पर मिधानि ने 16.55 लाख रुपये मूल्य की ट्रूनैट मशीन प्रायोजित की, जिससे टीबी के त्वरित निदान में मदद मिलेगी। साथ ही 1500 टीबी रोगियों को पोषण किट भी वितरित की गई। सीए एन. गौरी शंकर राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), मिधानि ने ट्रूनैट मशीन का उद्घाटन कर हैदराबाद के नारायणगुडा स्थित प्रिवेंटिव मेडिसिन संस्थान को सौंप दिया गया। इस कार्यक्रम में मिधानि के वरिष्ठ अधिकारी श्री ए रामकृष्ण राव, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), श्रीमती के मधुबाला, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), श्री हरिकृष्ण वी, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) और श्रीमती एआर रश्मि, वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन) सहित डॉ ए राजेशम, संयुक्त निदेशक (टीबी) और डॉ चलदेवी, राज्य टीबी नियंत्रण अधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए मिधानि की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विज्ञान वैभव 2025 में भागीदारी

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा हैदराबाद में 28 फरवरी से 2 मार्च, 2025 तक चले विज्ञान वैभव 2025, विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जिसमें मिधानि ने सक्रिय भागीदारी की। एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करने वाले विज्ञान वैभव 2025 में मिधानि की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए एक स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।

8 मार्च
महिला दिवस 2025

महिला दिवस समारोह

मिधानि में महिला कर्मचारियों की शक्ति, प्रतिभा और समर्पण को सम्मान स्वरूप 8 मार्च को महिला दिवस 2025 का बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजन संपन्न हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती स्पूर्ति रेड्डी, आईआरएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) रहीं, जिनके प्रेरणादायक संबोधन ने महिलाओं को कार्यस्थल और जीवन में सशक्त बनने का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला कर्मचारियों ने संवादात्मक चर्चाओं और टीम निर्माण गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। इसी क्रम में सीओई ऑडिटोरियम में डॉ. प्रवीण ज्योति द्वारा महिला स्वास्थ्य पर केंद्रित सत्र आयोजित किया गया। श्री एम.पी. रमेश और सीआईएसएफ सहायक कमांडेंट श्री राधेशाम राठौड़ ने शुभकामनाएं दीं। ये आयोजन वर्ष की थीम 'कार्रवाई में तेज़ी लाएं' का अनुसरण करते हुए समान अवसरों और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति मिधानि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का
56वां स्थापना दिवस समारोह

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (कें.औ.सु.ब.) ने 10 मार्च 2025 को हैदराबाद के मिधानि में अपने 56वें स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया। स्थापना दिवस परेड के मुख्य अतिथि सीए एन. गौरीशंकर राव, सी एंड एमडी (अतिरिक्त प्रभार) ने परेड की सलामी ली। अवसर पर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सीआईएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। मिधानि और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की। मिधानि के सी एंड एमडी (अतिरिक्त प्रभार) ने सीआईएसएफ कर्मियों की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त किया तथा कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण और बलिदान की सराहना की। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री टी. मुत्तुकुमार, निदेशक (उत्पादन एवं विपणन), श्री ए. रामकृष्ण राव, जीएम (एचआर), श्री हरिकृष्ण वी., एजीएम (एचआर), श्री एन. शेषगिरि राव, डीजीएम (सुरक्षा) और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। परेड का आयोजन सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट श्री राधेश्याम राठौर की देखरेख में किया गया।

मिधानि की सीएसआर परियोजनाएँ

मिधानि द्वारा विशाखापट्टणम में ग्रामीण शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित दो प्रमुख सीएसार परियोजनाओं को प्रायोजित करके उद्घाटन किया गया। समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में मिधानि के ये महत्वपूर्ण पहल हैं। एक – विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट, विशाखापट्टणम में चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन, जिससे ट्रस्ट में प्रयोगशाला उपकरणों में सुधार हो सके और स्थानीय समुदाय के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो सकें। दो - विशाखापट्टणम के उक्कुनगरम में चिन्मय मिशन विशाखापट्टणम के लिए तीन मंजिला इमारत का उद्घाटन, जिसे ग्रामीण शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन दोनों ही परियोजनाओं का उद्घाटन मिधानि के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) सीए एन. गौरी शंकर राव और हरि कृष्ण वी., अपर महाप्रबंधक (मा.संसा.) द्वारा किया गया।

एयरो इंडिया 2025 के दौरान मिधानि के अधिकारीगण रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित

रक्षा मंत्री के पीछे पहली लाइन में बाएँ से क्रमशः 4,5,6 व 7 – जे. शिव प्रसाद, वरि. प्रबंधक (फोर्ज व मशीन), के. रवि किरण, वरि. प्रबंधक (ओएस), एस रवि वर्मा, उप प्रबंधक (पीए), रतिराम नायक, उप प्रबंधक (गु.प्र.), अंतिम लाइन में बाएं से क्रमशः 5, 6 व 8 - अन्वेष कोथा, प्रबंधक (विपणन), आर. राकेश, उप प्रबंधक (मशीन शॉप) और ब्योमकेश साहू, उप महाप्रबंधक, (मेल्ट–II & III)

मिधानि में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

कंचनबाग, हैदराबाद-500058, भारत

हम हर जगह हैं मौजूद, समुद्र की गहराई से अंतरिक्ष की ऊँचाई तक